



प्रसंगवश

सौंदला गांव : अलग कुओं की परंपरा से साझा थाली तक का सफर

पूर्वा चिटणीस

महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सौंदला में शाम ढलते ही, एक जवान औरत अपने घर से चाय की ट्रे लेकर बाहर निकलती है और अपने बरामदे पर जमा हुए गांव के सरपंच समेत कुछ आदमियों को चाय के कप देती है। आदमी गर्म चाय पीते हैं, मुस्कुराते हैं और औरत को धन्यवाद देते हैं।

ग्रामीण महाराष्ट्र में यह एक सामान्य सा दृश्य है। लेकिन कुछ साल पहले तक वहां बैठे ये सभी 'ऊंची जाति' के पुरुष उस घर की देहलीज पर नहीं करते थे। अहिल्यानगर जिले के इस गांव में, जहां कभी जाति चुपचाप दूरी तय करती थी, वहां साथ बैठकर चाय पीना बराबरी का एक छोटा लेकिन बड़ा कदम बन गया है।

सौंदला ने एक साहसिक कदम उठाया है। 5 फरवरी को ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें गांव को 'जाति-मुक्त' घोषित किया गया। इस घोषणा में किसी से उसकी जाति पूछने पर रोक लगाई गई है। सार्वजनिक जीवन बिना ऊंच-नीच के साझा करने और इंसायनियत की भाषा बोलने पर जोर दिया गया है।

इस बदलाव की झलक छोटे-छोटे इशारों में दिखती है। दलित परिवार के घर पर साथ बैठकर चाय पीना बच्चों का बिना किसी पुरानी सीमा के साथ खेलना। लोहारों का अलग-अलग नहीं, बल्कि मिलकर मनाया जाना।

यह प्रस्ताव राजधानी मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के सरपंच द्वारा बुलाई गई विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। यह जिला पहले धुवीकरण और सामाजिक बहिष्कार की खबरों के लिए सुर्खियों में रहा है। सौंदला के सरपंच शरद शरद अगंडे ने कहा कि पड़ोसी इलाकों और पूरे

महाराष्ट्र में हाल के वर्षों में बढ़ते जातीय और सांप्रदायिक तनाव ने उन्हें जल्दी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। हम गाय को मां मानते हैं, लेकिन अपने ही जैसे इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर देते हैं। इसे बदलने की जरूरत है। लोग एक खास जाति के व्यक्ति से सामान खरीदने से मना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग निचली जाति के डॉक्टर से इलाज कराने से भी मना कर रहे हैं। यह सोच मेरे गांव में भी जड़ न जमा ले, इससे पहले मैं डरने लगा था। इसलिए मैंने कदम उठाने का फैसला किया।

ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों की तस्वीरें लगी हैं। अगंडे ने कहा कि इसका मकसद शिवाजी के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को दिखाना है और यह बताना है कि उन्होंने अपने मावलों में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। अगंडे के अनुसार, 'जाति-मुक्त गांव' का विचार उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद झिंजाडे ने सुझाया था। साथ ही उनके पिता का प्रभाव और उनकी पत्नी के प्रयासों ने भी सोच बदलने में भूमिका निभाई। सौंदला ने खुद को केवल जाति-मुक्त घोषित नहीं किया है, बल्कि ग्रामीणों ने अन्य सुधार भी किए हैं। जैसे गांव को गाली-गलौज और अपमानजनक शब्दों से मुक्त बनाना। विधवा विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

पड़ोसी बीड जिले का उदाहरण देते हुए, जहां इस समय मराठा और ओबीसी के बीच खुला तनाव चल रहा है, अगंडे ने कहा, 'आज हमारे राज्य में जो हो रहा है, वह बहुत चिंताजनक है। लोग बंट रहे हैं और दंगे हो रहे हैं। भविष्य में ऐसा लग रहा है कि हमें पाकिस्तान से नहीं, बल्कि एक-दूसरे से लड़ना पड़ेगा।' अहिल्यानगर

जिला, जिसे 2023 तक अहमदनगर कहा जाता था, पिछले दो वर्षों से कई गांवों में धुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को लेकर खबरों में रहा है। नफरत भरे भाषण, मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपील, और धार्मिक ढांचों को लेकर विवाद की खबरें आम रही हैं।

सौंदला की आबादी लगभग 2,500 है और यहां करीब 450 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत निवासी 'ऊंची जाति' से हैं और बाकी दलित हैं। करीब 4 परिवार मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 10 से 15 परिवार ईसाई धर्म मानते हैं। 5 फरवरी का प्रस्ताव अचानक नहीं आया। ग्रामीणों का कहना है कि अगंडे और उनकी पत्नी प्रियंका, जो पूर्व सरपंच रह चुकी हैं, ने धीरे-धीरे इसके लिए जमीन तैयार की।

अगंडे 2003 से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं। उनके पिता बाबा अगंडे गांव में अनुभवी कम्युनिस्ट नेता थे। जब अगंडे पहली बार 2003 में सरपंच बने, जो कि अब उनका तीसरा कार्यकाल है, तब उन्होंने गांव में प्रगतिशील विचार लागू करने शुरू किए। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समय के साथ सोच बदलने लगी, उन्होंने कहा। ग्रामिका ने कहा शुरुआत में मैं भी निचली जाति के लोगों के घर के अंदर जाने को लेकर संकोच में थीं। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने उनके घर पानी पी लिया। मैं हिचकिचाती थी। बदलाव की शुरुआत घर से होती है।

समय के साथ लोग एक-दूसरे के करीब आने लगे। दूरियां कम होने लगीं। जाति-मुक्त प्रस्ताव से दो महीने पहले गांव में एक और प्रतीकात्मक प्रस्ताव पास किया था। इसमें तय हुआ कि हर सुबह करीब 10 बजे मंदिर

के ऊपर लगे लाउडस्पीकर से राष्ट्रगान बजाया जाएगा। लोग अपने खेतों में काम करते हुए भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने लगे। अगंडे ने कहा, 'ऐसा करके मैं लोगों को बताना चाहता था कि हम पहले भारतीय हैं। हम सिर्फ अपने देश के बेटे हैं, जाति के आधार पर बंटे हुए नहीं।' पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, श्मशान घाट, पानी के स्रोत, स्कूल, कार्यक्रम और सरकारी सेवाएं सभी के लिए बराबर रूप से उपलब्ध होंगी। जाति या धर्म से जुड़े बयानों, धार्मिक बहिष्कार या जाति के आधार पर अन्याय को लेकर किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव नहीं होना चाहिए। गांव का कोई भी सदस्य सेशल मीडिया पर कोई भड़काऊ या आपत्तजनक पोस्ट साझा नहीं करेगा। अगर ऐसा करते पकड़ा गया तो सजा दी जाएगी। कई ग्रामीणों के मुताबिक सौंदला में खुला भेदभाव पहले ही कम हो चुका था। लेकिन बुजुर्गों को एक अलग समय याद है। 5 फरवरी के प्रस्ताव के बाद से ग्रामीण दो लोहार साथ मना चुके हैं, जिनमें शिव जयंती भी शामिल है। जाति-मुक्त घोषणा सौंदला का पहला सामूहिक सुधार नहीं है। ग्रामीणों ने गाली-गलौज पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी पास किया है। एक साल पहले गांव ने भेदभावपूर्ण विधवा प्रथाओं को औपचारिक रूप से हतोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन शुरू किया। एक अलग पहल के तहत गांव में छत्रों के लिए रोज दो घंटे का 'नो मोबाइल' समय अनिवार्य किया गया है। अगंडे ने कहा, 'बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सावधानी बरती जाए।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

उमंग और सामाजिक स्नेह का जीवंत महोत्सव है भगोरिया पर्व : मुख्यमंत्री

● मुख्यमंत्री आलीराजपुर जिले के उदयगढ़ के स्थानीय भगोरिया पर्व में हुए शामिल

पारंपरिक वेषभूषा, आमूषण और मांदल की थाप में रचा-बसा भगोरिया उत्सव



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि फाल्गुन मास के रंगों, मांदल की थाप और जीवन-प्रेम की उमंग से सराबोर भगोरिया पर्व जनजातीय संस्कृति, सामाजिक स्नेह और परंपरागत जीवन मूल्यों का जीवंत उत्सव है। इसको प्रत्यक्ष रूप से भगोरिया पर्व में शामिल होकर जिया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर के उदयगढ़ भगोरिया पर्व स्थल पर पारंपरिक लोकधुनों, नृत्य और उल्लासपूर्ण वातावरण ने सम्पूर्ण क्षेत्र को सांस्कृतिक रंगों से भर दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगोरिया पर्व जनजातीय संस्कृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मध्यप्रदेश सरकार जनजातीय परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। विरासत को विकास की राह पर ले जाने के संकल्प के साथ इस उल्लासपूर्ण पर्व को गरिमा और भव्यता के साथ मनाया गया। यह आयोजन जनजातीय संस्कृति की सशक्त पहचान और राज्य सरकार की संवेदनशील सोच को प्रतिबिंबित करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जनजातीय समाज एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा

पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्री जनजातीय संस्कृति के प्रतीक तौर कमान भेंट किया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्प-गुच्छ से स्वागत किया गया। मंत्री श्री द्वारा मंच से सभी को राष्ट्रीय पर्व भगोरिया की शुभकामनाएं दी। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह ने कहा कि अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में आयोजित स्थानीय भगोरिया पर्व में मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सहभागिता से उत्सव का उल्लास और अधिक बढ़ गया।

भगोरिया उत्सव में जनजातीय युवक-युवतियां रंग-बिरंगी पारंपरिक वेषभूषा में सजे-धजे दिखाई दिए। पुरुष वर्ग पारंपरिक धोती, अंगोछा एवं साफा धारण किए हुए थे, जबकि महिलाएं कांचली, चाघरा, ओढ़नी तथा पारंपरिक कढ़ाईयुक्त परिधानों में सुसज्जित रहीं। चांदी के हार, हांसली, कड़े, पायल, बिछिया एवं अन्य पारंपरिक आभूषणों की झंकार ने पर्व को भाव्यता प्रदान की। मांदल, ढोल एवं अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर कूर्ता कुर्राटियों के साथ लोकनृत्य करते जनजातीय समाज, सामूहिक उल्लास और आपसी मेल-जोल ने भगोरिया के माहौल को जीवंत एवं स्मरणीय बना दिया।

मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां को हार्ट अटैक

● भाईकीयादमें भतीजे को गले लगा कर रोई और थम गई सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं

झाबुआ (नप्र)। झाबुआ के सारंगी में मामेरा रस्म के दौरान दूल्हे की मां को दिल का दौरा पड़ गया। कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। मृतका की पहचान गायत्री पाटीदार के रूप में हुई है। दरअसल, महिला के बेटे गोलू की शादी बुधवार 25 फरवरी को थी। बारात बरवेटे गांव से दुल्हन लेकर लौट आई थी। गुरुवार को रिसेप्शन (स्वागत समारोह) रखा



गया था। सुबह के भोज के बाद दोपहर में मायरा कार्यक्रम था। इसी दौरान गायत्री के मायके वाले मामेरा की रस्म के लिए पहुंचे। परंपरा के मुताबिक, गायत्री अपने मायके वालों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ीं। गायत्री का एक ही भाई था। कई साल पहले गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। मामेरा की रस्म के लिए जब भतीजा पहुंचा था, तो उसे देखकर वह भावुक हो गईं वह भतीजे को गले लगाकर रोने लगीं। उनका बीपी लो रहता था। शादी की व्यस्तता के कारण वह दवा लेना भूल गई थीं। ज्यादा रोने और मानसिक तनाव के कारण उनका ब्लडप्रेशर गिर गया।

ब्लडप्रेशर में अचानक गिरावट के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा। विवाह के खुशी के माहौल में अचानक चीख-पुकार मच गई। अचानक तबीयत बिगड़ने पर गायत्री को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

subhassaverenews@gmail.com
facebook.com/subhassaverenews
www.subhassavere.news
twitter.com/subhassaverenews

शरद की सुबह

वस्तुतः	
मैं जो हूँ	तपना चाहिए
मुझे वहीं रहना चाहिए	अगर लोहा हूँ
यानी	हल बनने के लिए
वन का वृक्ष	बीज हूँ
खेत की मेड़	तो गड़ना चाहिए
नदी की लहर	फल बनने के लिए
दूर का गीत	मैं जो हूँ
व्यतीत	मुझे वह बनना चाहिए
वर्तमान में	धारा हूँ अन्तः सलिला
उपरिष्ठत भविष्य में	तो मुझे कुएँ के रूप में
मैं जो हूँ मुझे वहीं रहना चाहिए	खनना चाहिए
तेज गर्मी	ठीक जरूरतमंद हाथों से
मूसलाधार वर्षा	गान फैलाना चाहिए मुझे
कड़ाके की सर्दी	अगर मैं आसमान हूँ
खून की लाली	मगर मैं
दूब का हरापन	कब से ऐसा नहीं
फूल की जर्दी	कर रहा हूँ
मैं जो हूँ	जो हूँ
मुझे अपना होना	वही होने से डर रहा हूँ।
ठीक ठीक सहना चाहिए	- भवानी प्रसाद मिश्र

दिल्ली शराब नीति केस में कोर्ट ने

केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किया

कोर्ट बोला- चार्जशीट में खामियां, फैसले के बाद केजरीवाल रोते हुए बोले- जिंदगीभर ईमानदारी कमाई



नई दिल्ली (एजेंसी)। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राजज एवैन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राजज एवैन्यू कोर्ट ने शुरुआत को कहा- दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया।

हमारे खिलाफ साजिश...

मोदी, शाह, राहुल गांधी का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल ने जमकर साधा निशाना- कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने हमारे खिलाफ साजिश रची। हम कट्टर ईमानदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी और प्रतिष्ठा अर्जित की और मोदी- शाह इसे धूमिल करना चाहते थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो दिल्ली में दौबारा चुनाव कराएं। आज चुनाव हुए दिल्ली में 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी।



टीएमसी ने केंद्रीय एजेंसियों के 'दुरुपयोग' के लिए बीजेपी को आड़े हाथों लिया- तुणमूल कांग्रेस ने शुरुआत को दिल्ली की एक अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में बरी करने के फैसले का स्वागत किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया।

- स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाया- स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने इस केस का फैसला सुनाया। वे दिल्ली कोर्ट के एक अनुभवी जज हैं। वे दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस के एक सीनियर न्यायिक अधिकारी हैं। अभी वे नई दिल्ली के राजज एवैन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज (पीसी एक्ट) सीबीआई-01 के पद पर तैनात हैं।
- दिल्ली शराब नीति केस में यह 23 लोग बरी हुए- अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के. कविता, दुर्गाशा पाठक, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिछई, मूथा गीतम, समीर महेंदर, अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे, बुचिबाबू गोरतला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर, शरत रेड्डी।

कांग्रेस विधायक ने किया

विधानसभा में शीर्षासन

● हर्ष फायरिंग पर एफआईआर को लेकर जताया विरोध, सदन से कांग्रेस ने किया वॉकआउट ● बोले- पटाखा भी फोड़ू तो केस



भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुरुआत को नजारा कुछ ऐसा था कि हर कोई दंग रह गया। कार्यवाही चल रही थी और इसी बीच श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू लाल जंडेल अचानक सिर के बल खड़े हो गए। सदन के भीतर विधायक जी का यह शीर्षासन देखकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के माथे पर बल पड़ गया। जंडेल का आरोप है कि सरकार और पुलिस मिलकर उन्हें और उनके कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों के जाल में फंसा रही है।

एक महीने में 3 केस, अब तक 15 मामले- बाबू जंडेल का कहना है कि पिछले एक महीने में ही उनके खिलाफ तीन नई एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं, जिससे उनके ऊपर दर्ज केसों की कुल गिनती 15 तक

पहुंच गई है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के नेता खुलेआम फायरिंग करते हैं, नाचते-गाते हैं, उन पर कोई आंच नहीं आती। लेकिन जब मैं शिव बारात में एक पटाखा फोड़ देता हूँ, तो पुलिस तुरंत केस ठेक देती है। उनका दावा है कि वे जनता और किसानों की आवाज उठाते हैं, इसलिए सरकार उन्हें निशाना बना रही है।

मर जाऊंगा, पर डरूंगा नहीं- उग्र अंदाज में विधायक जंडेल ने साफ कह दिया कि वो जेल जाने या गोली खाने से नहीं डरते। गांधी प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज गांधी जी होते, तो ये अन्याय देखकर रो पड़ते। जंडेल ने चेतावनी दी है कि अगर ये फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे।



कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में भूकंप, 5.4 तीव्रता

● तेज झटके महसूस हुए, इमारतें हिलीं, लोग सड़कों पर निकले

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई जिलों में शुक्रवार दोपहर करीब 1.30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के दाका स्थित अग्रगांव में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। पश्चिम बंगाल से अग्रगांव की दूरी लगभग



26 किलोमीटर बताई जा रही है। झटके इतने तेज थे कि कोलकाता में बहुमंजिला इमारतें कुछ सेकेंड तक हिलती रहीं। अचानक कंपन महसूस होते ही लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

एआईएडीएमके से निष्कासित तमिलनाडु के पूर्व सीएम पन्निरसेल्वम डीएमके में शामिल

मुख्यमंत्री स्टालिन ने सदस्यता दिलाई

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व एआईएडीएमके नेता ओ पन्निरसेल्वम (ओपीएस) ने शुक्रवार को डीएमके का दामन थाम लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी जॉइन की। यह कदम अप्रैल-मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले उठाया



गया है। ओपीएस तीन बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे दिवंगत नेता जे जयललिता के करीबी माने जाते थे।

2 दिन के इजराइल दौरे से लौटे पीएम मोदी

● दोनों देशों के बीच 27 एमओयू और एग्रीमेंट हुए



नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दो दिन के स्टेट विजिट के बाद शुक्रवार रात 1 बजे भारत लौट आए। यह नौ साल में उनका पहला विजिट था। इस दौरान दोनों देशों ने

अपने आपसी रिश्तों को एक स्पेशल स्टेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। अलग-अलग सेक्टर में 27 एमओयू और एग्रीमेंट पर साइन हुए।

बंगाल में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन हाई कोर्ट से मिली 'परिवर्तन यात्रा' की सशर्त अनुमति; शाह दिखाएंगे हरी झंडी

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित 'परिवर्तन यात्रा' को लेकर चल रही कानूनी रस्साकशी के बीच कोलकाता हाई कोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति शुभा घोष की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि एक ओर दो मार्च को दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक यात्रा निकाली जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थान पर एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए।

यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर 'हिंदू रक्षा दल' ने लिखी विवादित बात



नई दिल्ली (एजेंसी)। देहरादून एक्सप्रेस-वे पर लिखे गए एक आपत्तिजनक स्लोगान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंदू रक्षा दल के लोग लिख रहे हैं, 'यह रोड मुसलमान के लिए नहीं है'। इस मामले ने क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

प्रशासन ने दीवार से हटाए आपत्तिजनक शब्द

मीडिया टीम ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। हालांकि दीवारों पर लिखे गए शब्दों को बाद में मिटा दिया गया है, लेकिन उनके निशान अभी भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।

हिंदू रक्षा दल ने ली जिम्मेदारी

इस पूरे मामले में हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है। संगठन के कुछ सदस्यों का दावा है कि उनकी महिला विंग ने यह नारे लिखे थे।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान में जंग



काबुल/इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी है। लेकिन इस पर भी खुद उन्हीं को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में घुसकर भीषण हमला कर डाला है। इस्लामाबाद में मौजूद पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया गया।

इस ड्रोन हमले में बम से अटक किया गया। उसमें हुए नुकसान की अभी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इससे कम से कम पाकिस्तान की पोल खुल गई, जो चीन से मिले अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ा गुमान किया करता था।

पाकिस्तानी सेना तालिबान के हाथों बुरी तरह से पिटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात जंग जैसे हो गए हैं।

राजपुर में बड़ा बस हादसा

हाईवे से फिसलकर खेत में घुसी यात्री बस, 14 घायल

बड़वानी (नप्र)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के राजपुर में शुक्रवार को एक बड़ा यात्री बस हादसा सामने आया, जब खंडवा से बड़वानी जा रही एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे खेत में जा घुसी। इस हादसे में 14 यात्री घायल हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो घटना को स्पष्ट कर रहा है। राजपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि खंडवा-वडोदरा हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के पास यह दुर्घटना हुई। बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और सीधे खेत में जा घुसी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

भयावह था सीन, दौड़कर पहुंचे लोग यात्रियों को



निकाला- हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और पुलिस के साथ मिलकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस जिस रफ्तार से नीचे उतरी, वह दृश्य बेहद भयावह था। थाना प्रभारी ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि गनीमत रही कि बस सड़क और खेत के बीच लगे पेड़

से नहीं टकराई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

यात्रियों को फेंकर आए हैं, 9 रेफर- सभी 14 घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया गया। बीएमओ डॉ. देवेन्द्र रोमड़े के अनुसार, कुछ यात्रियों में फेंकर की आशंका को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद 9 घायलों को जिला अस्पताल बड़वानी रेफर किया गया है।

मधुबनी मेडिकल कॉलेज का फरमान

रमजान में साथ दिखे छात्र-छात्रा तो करा दिया जाएगा निकाह



छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है।

मधुबनी मेडिकल कॉलेज के सर्कुलर में दी गई निकाह की चेतावनी- मिली जानकारी के अनुसार, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी इस पत्र में रमजान के महीने का हवाला दिया गया है। सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि रमजान के पाक महीने के दौरान कोई भी लड़का और लड़की (कपल)

मधुबनी (एजेंसी)। बिहार के मधुबनी मेडिकल कॉलेज का एक अजीबोगरीब और विवादित सर्कुलर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कॉलेज प्रशासन ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर छात्र-छात्राओं के साथ खड़े होने पर न केवल पाबंदी लगाई है, बल्कि उल्लंघन करने पर सीधे निकाह करा देने की चेतावनी दी है। इस तुलसी फरमान के सामने आने के बाद संस्थान के छात्र-छात्राओं में हड़कंप मचा हुआ है।

अदालत का विस्तृत आदेश रात तक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो सकता है। इसी आदेश में यह भी उल्लेख होगा कि मार्च के तीसरे सप्ताह में अगली सुनवाई किस तारीख को होगी। तब तक दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की

शंकराचार्य की अर्जी पर फैसला सुरक्षित गिरफ्तारी पर रोक, पुलिस को पूछताछ की छूट

इलाहाबाद (एजेंसी)। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से होगा। जस्टिस जे.के. सिन्हा की बैंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ और महामहगमी के कारण सुनवाई चेंबर में की गई, जहां केवल केस से जुड़े वकील मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने

बचाव पक्ष से यह भी पूछा कि पहले सेशन कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया और सीधे हाईकोर्ट आने का औचित्य क्या है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने मुख्य रूप से अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।

जाएगी, हालांकि पुलिस चाहे तो पूछताछ कर सकती है और शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जस्टिस जे.के. सिन्हा की बैंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ और महामहगमी के कारण सुनवाई चेंबर में की गई, जहां केवल केस से जुड़े वकील मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने

बचाव पक्ष से यह भी पूछा कि पहले सेशन कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया और सीधे हाईकोर्ट आने का औचित्य क्या है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने मुख्य रूप से अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।

इस्लामाबाद पर हमला.., तालिबान लड़ाकों ने कहर मचा दिया!

● पाक बोला- 133 अफगान लड़ाके मारे, तालिबान के समर्थन में भारत ● परमाणु ठिकाने और पीएम हाउस तक पहुंचे तालिबान ड्रोन ● पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने युद्ध की औपचारिक घोषणा की

55 पाकिस्तानी सैनिकों को किया डेर

टोलो न्यूज के मुताबिक तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 'गजब लिल हक' नाम का ऑपरेशन शुरू किया और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमलों में 274 अफगान लड़ाके मारे गए, जबकि 400 से ज्यादा घायल हैं। दोनों तरफ से करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। भारत ने भी पाकिस्तान के हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान का समर्थन किया है। गुरुवार रात से पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़पें शुरू हुई हैं, जब तालिबान ने पाकिस्तानी मिलिट्री ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इसके बाद दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और काबुल की ओर से ड्रोन हमला किया गया।

● तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी जेट गिराया, 19 चौकियों पर कब्जा- अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट भी मार गिराया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास हैं। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है।

● अफगानिस्तान आर्मी पाकिस्तान सेना को दे रही है कड़ी चुनौती - अफगानिस्तान ने कथित तौर पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया है। गुरुवार शाम को बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ने के बाद अफगानिस्तान की ओर से शुक्रवार को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी ऑफिसर आदिल राजा का दावा है कि अफगानिस्तान से आए ड्रोन ने इस्लामाबाद के पास पाकिस्तानी मिलिट्री शासन के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तानी आर्मी के आलोकच और ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे आदिल राजा का कहना है कि अफगानिस्तान से लॉन्च किए गए ड्रोन ने पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर उसके प्रमुख शहरों पर हमले किए हैं। राजा का कहना है कि तालिबान के ड्रोन जमरूद मिलिट्री बेस, नौशेरा किला, स्वाबी में पुलिस स्टेशन और इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर तक पहुंचे हैं।

नवोन्मेष 2026: 12 से 15 मार्च तक होगा आयोजन

भोपाल। मध्य भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में इनोवेशन कनिवाल 'नवोन्मेष 2026' का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना है। यह अटल इन्क्यूबेशन सेंटर-रबीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी (एआईसी-आरएनटीयू) द्वारा स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें छात्र, स्टार्टअप, बिजनेस लीडर्स, निवेशक और नीति निर्माता और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े सभी लोग शामिल होंगे। प्रतिभागियों के लिए इसमें 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीतने का मौका होगा।

नवोन्मेष 2025 प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, निवेशकों और स्टार्टअप सलाहकारों से संपर्क करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें निरंतर विकसित हो रहे व्यवसाय और प्रौद्योगिकी परिदृश्य में मूल्यवान जानकारी प्राप्त हो सके। पैन्ल चर्चाओं, व्यावहारिक कार्यशालाओं और मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेष 2026 उपस्थित लोगों को उनके विचारों और उपक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान, कौशल और संसाधनों से लैस करेगा। है। अधिक जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए, पर जाएं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च है।

स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि नवोन्मेष 2026 केवल एक छात्र उत्सव नहीं, बल्कि युवाओं की रचनात्मक क्षमता, उद्यमिता और तकनीकी नवाचार को वास्तविक अवसरों से जोड़ने वाला एक सशक्त मंच है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पहली बार कॉम्बैट हेलिकॉप्टर की उड़ान भरी

जैसलमेर (एजेंसी)। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (जैसलमेर) में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 'वायु शक्ति-2026' शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने जैसलमेर की सीमावर्ती एयरसेस में पहली बार किसी लड़ाकू हेलिकॉप्टर को को-पायलट



किया। राष्ट्रपति पोखरण रेंज पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'वायु शक्ति' युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। मुर्मू 26 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे।

वायु शक्ति-2026 में प्रचंड के अलावा राफेल, सुखोई-30 एमकेआई और अपाचे का कारण सुनवाई चेंबर में की गई, जहां केवल केस से जुड़े वकील मौजूद रहे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने

राफेल: एक डबल इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर एयर क्राफ्ट है। ये हवा से हवा, हवा से जमीनी हमले कर सकता है।

सुखोई: सुखोई एसयू-30 एमकेआई दो इंजन वाला लड़ाकू विमान है जिसे भारतीय वायु सेना के लिए रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो के साथ लिखा गया है कि सुहागरात के दिन दुल्हन ने कम्मरे में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका प्रेमी आ रहा है, वह उसके साथ जाएगी। इसके बाद सास ने मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग दुल्हन के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग सास की गई मारपीट का आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि चाहे मामला कुछ भी हो, किसी को भी हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे परिवार की निजी बात बता रहे हैं।

दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई

हमीरपुर (एजेंसी)। आजकल सोशल मीडिया पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो लोगों को हंसा देते हैं, तो कुछ हैरान कर देते हैं। कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर सच क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है। वीडियो में शादी के बाद की एक घटना दिखाई दे रही है, जहां परिवार के



लोग एक कम्मरे में बैठे नजर आ रहे हैं। माहौल सामान्य नहीं दिख रहा, बल्कि बहस और तनाव का माहौल दिखाई देता है। इसी दौरान सास और नई दुल्हन के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल जाती है।

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कम्मरे में कई रिश्तेदार मौजूद हैं। नई नवेली दुल्हन और उसकी सास आमने-सामने बैठे हैं। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि दुल्हन ने सुहागरात मनाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह कम्मरे में नहीं जाएगी।

मेरा प्रेमी आना वाला है... कथित तौर पर दुल्हन ने यह भी कहा कि उसका प्रेमी आने वाला है और वह उसके साथ जाना चाहती है। यह बात सुनकर माहौल और ज्यादा गरम हो गया। इसके बाद सास गुस्से में आ गई और उसने दुल्हन को मारना-पीटना शुरू कर दिया।

नृत्य के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा कुत्ता

● पद्मश्री कलाकारों ने जताई नाराजगी खजुराहो में 7 दिवसीय 52वें नृत्य समारोह का समापन



खजुराहो (नप्र)। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का विश्व प्रसिद्ध खजुराहो 52वें नृत्य महोत्सव का गुरुवार शाम समापन हो गया था। यह महोत्सव संस्कृति विभाग एवं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की ओर से आयोजित किया गया। इस सात दिवसीय उत्सव की अंतिम शाम पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नृत्यांगनाओं को कला से सजी रही। हालांकि, महोत्सव के प्रबंधन को लेकर दर्शकों में नाराजगी भी देखी गई।

वीआईपी कुर्सियां खाली रहीं, नाराज हुए विदेशी पर्यटक- स्थानीय और बाहर से आए पर्यटकों ने आरोप लगाया कि वीआईपी के नाम पर कुर्सियां ब्लॉक रखी गईं, जबकि वे घंटों देरी से पहुंचे। इसके अलावा, शुभारंभ के दिन संस्कृति मंत्री के लंबे भाषण और देरी के कारण विदेशी सैलानियों ने हूटिंग कर अपना विरोध दर्ज कराया था।

पर्यटक बोलें-कार्यक्रम शानदार

पर्यटक अमित मेदीराता ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, यहां की वाइस बहुत अच्छी है और कार्यक्रम 'नेक्स्ट लेवल' के हैं, लेकिन पब्लिसिटी शून्य है। सड़कों पर कोई पोस्टर नहीं है, जिससे सीटें खाली रहती हैं। जब कोई कलाकार इतनी मेहनत करके स्टैंड पर परफॉर्म करता है और उसे सामने से वैसी दाद या तालियां नहीं मिलतीं, तो उसका मनोबल गिरता है। मेरी गुजारिश है कि इसकी बेहतर मार्केटिंग और पब्लिसिटी की जाए।

बच्चों में बढ़ते तनाव पर जागरूकता कार्यक्रम



भोपाल। सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र द्वारा आंगनवाड़ी 1146 गोविंदपुरा में कॅरियर को लेकर बच्चों में बढ़ते तनाव और आत्महत्या की रोकथाम के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कार्डसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र की निदेशिका रिमता कुमारी ने बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ कॅरियर चयन के लिए प्रक्रिया पर तकनीकों की चर्चा की। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखकर परीणाम के लिए और उसके बाद भविष्य के लिए बेहतर रणनीति कैसे बनाएं इस पर चर्चा करते हुए लड़कियों को शिक्षित और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लाभ बताए गए। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता सविता वर्मा, सहायिका निशा, 14 बच्चे और 10 अभिभावक उपस्थित हुए। गौरतलब है कि रिमता कुमारी पिछले ग्यारह सालों से मानसिक स्वास्थ्य पर अपने केंद्र से कई जागरूकता कार्यक्रम करती रही हैं। हर महीने अलग-अलग विषय पर आंगनवाड़ी में निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं।

बड़े तालाब के किनारे बने रसूखदारों के बंगलों पर चलेगा बुलडोजर ?

डेडलाइन के साथ नया सर्वे शुरू, एडीएम कर रहे लीड

भोपाल (नप्र)। एसडीएम की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमों अपर लेक के फुल टैंक लेवल से नो-कंस्ट्रक्शन जोन की पहचान करने और उस एरिया में कब्जों की पहचान करने के लिए एक और सर्वे कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह काम आखिरकार अपने लॉजिकल नतीजे पर पहुंचेगा। अपर लेक के आसपास के कब्जों को हटाने का काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और कोर्ट के निर्देश पर पहले कम से कम तीन बार किया जा चुका है और फिर भी अपर लेक के किनारों पर कब्जे साल भर में बढ़ते रहे हैं।

ये इलाके हैं नो-कंस्ट्रक्शन जोन- लेक के फुल टैंक लेवल से 50 मीटर का एरिया, जो भोज वेटलैंड और रामसर साइट का भी हिस्सा है, वेटलैंड नियमों के तहत नो-कंस्ट्रक्शन जोन है और अभी भी इस जोन में सैकड़ों फार्म हाउस, बंगले, मैरिज हॉल, रेस्टोरेंट से लेकर छोटे घर और झुगियां बनी हुई हैं। इन सब में बिशनखेड़ी, सूरज नगर, खानुगांव, बैरागढ़ और ऐसे एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

टास्क फोर्स ने नया सर्वे शुरू किया- डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा बनाई गई 17 लोगों की टास्क फोर्स को एडीएम अंकुर मेथ्राम लीड कर रहे हैं। यह टीम झील के आसपास के मना किए गए



एरिया में सर्वे और डिमाकेशन और बाद में पहचाने गए अतिक्रमणों को हटाने के प्रोसेस पर नजर रखेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बार अतिक्रमण हटाने को लेकर सीरियस है, तो उन्होंने कहा, प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। अगर आपके मन में कोई ख़ास स्ट्रक्चर है और जब उसे गिरा दिया जाता है, तभी आप मानेंगे कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह एक अलग बात है।

27 फरवरी को एक और मीटिंग- उन्होंने कहा कि, मैं यह साफ कर दू कि टास्क फोर्स न तो

सर्वे में शामिल होगी और न ही अतिक्रमणों को गिराने में शामिल होगी। यह काम संबंधित सरूख की लीडरशिप वाली टीमों को करना है और वे काम पर हैं। जब हम बात कर रहे हैं, तब एसडीएम, टी टी नगर, अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं न कहीं तोड़फोड़ कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि जब हाल ही में दो बार सर्वे हो चुका है, तो सर्वे क्यों जरूरी है, तो उन्होंने कहा, अगर कोई एसडीएम कहता है कि उसके पास इलाके में अतिक्रमण की पूरी लिस्ट है और इलाके में सीमांकन भी पूरा हो गया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां काम अधूरा है, उन्हें इसे

मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक श्रीमती सुलोचना रावत के स्वास्थ्य का जाना हालचाल

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व विधायक श्रीमती सुलोचना रावत के निवास स्थल पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने श्रीमती रावत के परिजनों से भी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पूर्व विधायक के गृह निवास पहुंचने पर परिजनों द्वारा उनका तिलक लगाकर पुष्प-गुच्छ से आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को आलीराजपुर जिले की जोबट तहसील के ग्राम कानाकाकड़ में पूर्व विधायक श्रीमती रावत के निवास पहुंचे। उन्होंने परिजनों से उपचार की विस्तृत जानकारी ली। उनके पुत्र श्री विशाल रावत व परिजनों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कठिन समय में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती रावत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि सरकार संकट की इस घड़ी में परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से खड़ी है। इस अवसर पर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागरसिंह, पूर्व सांसद श्री गुमानसिंह डामोर, संभागयुक्त इंदौर डॉ. सुदाम खांडे, कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर, पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।



भोपाल में 239 करोड़ बढ़ेगी शराब ठेकों की कीमत

87 दुकानों के लिए 1432 करोड़ का टारगेट, 2 मार्च को 29 दुकानों की नीलामी



भोपाल (नप्र)। अबकी बार भोपाल की 87 शराब ठेकों से सरकार को 239 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा मिल सकते हैं। पिछले साल रिजर्व प्राइस (आरपी) 1073 करोड़ रुपए थी, जबकि उच्चतम ऑफर राशि 1139 करोड़ रुपए मिली थी। इस बार रिजर्व प्राइस ही 1432 करोड़ रुपए रखी गई है। 2 मार्च को 29 दुकानों की नीलामी होगी।

बता दें कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है। नई व्यवस्था में शराब दुकानों को छोटे-छोटे समूहों में बांटा गया है। भोपाल की 87 दुकानों को 20 ग्रुप में बांटा है। जिनके आवंटन की प्रक्रिया ई-टेंडर के जरिए होगी।

इनमें से 7 ग्रुप की 29 दुकानों के लिए

पहले फेज में टेंडर की प्रोसेस शुरू की गई है। 2 मार्च को सुबह 10.30 से दोपहर 2 बजे तक टेंडर सबमिट होंगे। इसी दिन शाम 6 बजे से डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मौजूदगी में टेंडर खोलने की कार्यवाही होगी।

इन ग्रुपों के लिए प्रक्रिया- बागसेवनिया ग्रुप की 5 दुकान, हबीबगंज फाटक ग्रुप की 4 दुकान, भानपुर चौराहा ग्रुप की 5 दुकान, स्टेशन बजरिया ग्रुप की 5 दुकान, खजूरीकलां ग्रुप की 3 दुकान, जहांगीराबाद ग्रुप की 4 दुकान और गुनगा ग्रुप की 3 दुकानों के लिए यह टेंडर प्रक्रिया की जा रही है।

20 प्रतिशत बढ़ी ठेके की कीमत- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नीलामी की

प्रक्रिया में ठेके 1193 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुए थे, जो टारगेट से 11 प्रतिशत यानी, 120 करोड़ रुपए अधिक थी। इस बार 1432 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस रखी गई है।

बता दें कि वर्तमान मूल्य में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी कर आरक्षित मूल्य तय किया गया है। इसका असर अब समूहों की कीमतों पर दिखने लगा है। भोपाल में इस बार सबसे महंगा समूह पिपलानी का है। इसमें 4 दुकानें - पिपलानी, अयोध्या नगर, रत्नागिरी तिराहा और पटेल नगर हैं। 20 फीसदी आरक्षित मूल्य बढ़ने के बाद इस समूह की कीमत 127 करोड़ 77 लाख 60 हजार 551 रुपए हो गई है। इससे पहले वर्ष 2025-26 में इन दुकानों का वार्षिक मूल्य 106 करोड़ 48 लाख से ज्यादा था।

इसी तरह बागसेवनिया समूह की कीमत करीब 101 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हो गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नीति में किए गए बदलावों के आधार पर ही ई-टेंडर के जरिए दुकानों का आवंटन होगा। छोटे समूह बनाए जाने से ज्यादा बोलीदाता सामने आएंगे व सरकार को फायदा मिलेगा। इससे नए लोगों को भी भागीदारी का मौका मिलेगा।

239 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे

विभाग की माने तो नई व्यवस्था से सरकार के खजाने में सीधे 238 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। टेंडर फाइनल होने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।

रीवा में विमानन सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण कार्यों की उप मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

भोपाल। रीवा में विमानन सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों की उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में विमानन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि रीवा से रायपुर एवं कोलकाता के लिए नई हवाई सेवाएं प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करें, ताकि उड़ान सेवाएं जल्द से जल्द प्रारंभ की जा सकें। साथ ही, रीवा-इंदौर-रीवा एवं

व्यक्त की गई है। प्राप्त बिड़स का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण वर्तमान में प्रगति पर है, ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र निर्णय लिया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रस्तावित हवाई सेवाओं से रीवा सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक एवं पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्रीय संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। चिकित्सकों के प्रमोशन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही के लिए निर्देश



बैठक में चिकित्सकों के प्रमोशन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस विषय में शीघ्र निर्णय लेकर प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके। बैठक में अपर मुख्य सचिव, विमानन एवं सामान्य प्रशासन श्री संजय कुमार शुक्ल, अपर सचिव सामान्य प्रशासन श्री अजय कटेशरिया और उप सचिव, विमानन श्री कैलाश बुंदेला सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

10वीं का पेपर देने जा रही 15 वर्षीय छात्रा की मौत, बाइक से टकराकर पलटाई-रिक्शा

शराब के नशे में सीढ़ियों से गिरा युवक, मौत

● जाँब छूटने के बाद से तनाव में था, नई नौकरी की तलाश में जुटा था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के छेला मंदिर इलाके में दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से गिरकर युवक की मौत हो गई। हदसा गुरुवार देर रात हुआ। युवक शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था। दो महीने पहले उसकी नौकरी चली गई थी। इससे वह तनाव में रहने लगा था। लगातार प्रयासों के बाद भी दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मधुर नामदेव (36) कमल किशोर नामदेव कैची छेला फाटक के करीब रहता था।

कई शोरूम में रिज्यूम दिया था- वह पूर्व में जिंसी के एक कार शोरूम में बतौर इन्फ्रेंडर जाँब करता था। दो महीने पहले उसे जाँब को छोड़ना पड़ा था। जिसके बाद से ही नई जाँब को सच कर रहा था। लगातार कई शोरूम में रिज्यूम दे रहा था। हालांकि कहीं भी उसे जाँब कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था।

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर जिले के नौगांव में एक बेहद दुखद सड़क हादसे में 10वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा की जान चली गई। छात्रा ई-रिक्शा में सवार होकर अपना बोर्ड का पेपर देने जा रही थी, तभी ईसानगर चौराहे के पास ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक बाइक से टकराकर पलट गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से होनहार बेटी के परिवार में मातम पसर रहा है।

जानकारी के अनुसार, मऊसहानिया गांव की रहने वाली 15 वर्षीय दीपा अहिरवार (पिता सोनू अहिरवार) 10वीं कक्षा की छात्रा थी। वह अपना पेपर देने के लिए ई-रिक्शा से नौगांव के लिए निकली थी। रास्ते में ईसानगर चौराहे पर पहुंचते ही ई-रिक्शा चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया।

खड़ी बाइक से जोरदार टक्कर के बाद पलटाई-रिक्शा- अनियंत्रित होने के बाद ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल

में जोरदार टक्कर मारते हुए पलट गया। इस हादसे में ई-रिक्शा सवार दीपा बुरी तरह से घायल हो गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया था दम- हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मदद करते हुए गंभीर रूप से घायल छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (नौगांव) पहुंचाया। वहां प्राथमिक जांच के बाद बीएमओ डॉ. रविंद्र पटेल ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक, छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था और अस्पताल लाते समय तक उसकी सांसें थम चुकी थी।

होनहार थी दीपा, पुलिस कर रही रिक्शा चालक से पूछताछ- हादसे में बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और परिजन बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे।

छात्रा के चाचा सूरज अहिरवार ने बताया कि दीपा पढ़ाई-लिखाई में काफी होनहार थी। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने ई-रिक्शा चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

छात्राएं बोली- गोद में बैठाते हैं

छतरपुर में सरकारी प्राइमरी स्कूल का टीचर पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार

छतरपुर (नप्र)। छतरपुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में 6 से ज्यादा छात्राओं से छेड़छेड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर ये छात्राएं रोती हुई घर लौटीं। परिजनों से कहा- क्लास में शिक्षक उनके साथ बहुत ही गंदी हरकत करते हैं। मास्टर जी गोद में बिठाते हैं। अंडरगार्मेंट्स में हाथ डालते हैं।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी टीचर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आई थीं, लेकिन इस बार छात्राओं की मानसिक स्थिति और डर को देखकर मामला गंभीर लगा। परिवारों ने तय किया कि वे सीधे स्कूल जाकर शिक्षक से बात करेंगे।

गुरुवार दोपहर गांव के कई परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक से जवाब मांगा। माहौल धीरे-धीरे तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख किसी ने डायल 112 पर सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को भीड़ से निकालकर थाने ले गई।

संपादकीय

आप की नैतिक जीत

दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली की रऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री मनीष सिंसोदिया सहित सभी 7 आरोपियों को बरी किया जाना आम आदमी पार्टी की नैतिक जीत है। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है। हालांकि इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की बात कही है, लेकिन यह संदेह शुरू से ही था कि यह पूरा मामला भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए है और पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका फायदा मिला। उसने 11 साल से दिल्ली में जमी आप सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति घोटाले की हज़ारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। सीबीआई सिंसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में भी मामला साबित नहीं कर पाई। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ गया।

चार्जशीट में ऐसी कई बातें शामिल की गईं, जिनका गवाहों के बयानों से कोई संबंध नहीं है। चार्जशीट में विरोधाभास हैं, जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए जज ने कहा कि हेरानो की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री नहीं थी। गौरतलब है कि मनीष सिंसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और न ही उनके खिलाफ कोई बयानदगी हुई। उल्लेखनीय है कि पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर CAG (कम्प्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) की रिपोर्ट लीक हुई थी। इसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब नीति में काफी गड़बड़ियां थीं, जिनमें लाइसेंस देने में खामी भी शामिल है। इसके साथ ही आप नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टरों की अगुआई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उपराज्यपाल के खिलफ ED और CBI दोनों जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था। ED ने उन्हें 21 मार्च 2024 को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने भावुक होकर कि आज सत्य की जीत हुई है। ये केस झूठा था। जाहिर है कि दिल्ली कोर्ट के फैसले से इस धारणा को पुष्टि हो गई है कि पूरा मामला भ्रष्टाचार और अनियमितता का कम और राजनीतिक साजिश का ज्यादा था। इस फैसले से जहां सीबीआई कार्यक्षमता पर एक बार फिर प्रशंसित है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। आम आदमी पार्टी को इस फैसले का लाभ अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। उनकी नैतिक जमीन मजबूत हुई है। अब आप ने भी सीबीआई के खिलाफ ऊंची अदालत में जाने का एलान कर दिया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार - लोकतंत्र की बड़ी चुनौती



कि सी भी लोकतांत्रिक समाज में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणामों वाला विषय होता है। हाल के समय में भारत में यह बहस तेज हुई कि क्या आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। यह विवाद तब सामने आया जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से एक संशोधित अध्याय शामिल किया गया। इस अध्याय की प्रस्तुति को लेकर देश के प्रधान न्यायाधीश ने आपत्ति जताई और संकेत दिया कि यह विषय जिस तरह से रखा गया है, वह एक सोची-समझी कोशिश भी हो सकती है। यद्यपि यह बहस जारी है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों और घटनाओं को केवल पाठ्यपुस्तक से हटकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता।

न्यायपालिका किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में अत्यंत सम्मानित और विशिष्ट स्थान रखती है। वह संविधान की संरक्षक होती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और राज्य तथा नागरिकों के बीच उत्पन्न विवादों का अंतिम निर्णय देती है। इसलिए न्यायपालिका को निष्पक्षता और ईमानदारी पर जनता का विश्वास लोकतंत्र की स्थिरता की आधारशिला है। कार्यपालिका और विधायिका जहाँ राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, वहीं न्यायपालिका को वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी सदस्य पर भी अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। हाल के वर्षों में कुछ मामलों ने न्यायिक जवाबदेही को

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया 'सिद्ध दुराचार या अक्षमता' के आधार पर संसद द्वारा पूरी की जाती है। किंतु इस प्रक्रिया की शर्तें अत्यंत कठोर हैं। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इतिहास में देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में अंत तक पहुंची है। कई बार न्यायाधीशों ने प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, और कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि इन कठोर प्रावधानों का उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है, फिर भी इससे यह धारणा बनती है कि जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।

लेकर असहज प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद काफी चर्चा में रहा। समाचारों में यह आरोप सामने आया कि उनके निवास से करोड़ों रुपये के आंशिक रूप से जले हुए नोट बरामद हुए। यद्यपि उनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ किए जाने की बात कही गई, परंतु अभी तक वह अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है और वे पद पर बने हुए हैं। यह मामला ही नहीं, बल्कि अतीत में अन्य न्यायाधीशों से जुड़े आरोप भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि गंभीर आरोपों की जांच और दंड की प्रक्रिया कितनी जटिल और लंबी है।

भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया 'सिद्ध दुराचार या अक्षमता' के आधार पर संसद द्वारा पूरी की जाती है। किंतु इस प्रक्रिया की शर्तें अत्यंत कठोर हैं। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। इतिहास में देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में अंत तक पहुंची है। कई बार न्यायाधीशों ने प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, और कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। यद्यपि इन कठोर प्रावधानों का उद्देश्य न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाना है, फिर भी इससे यह धारणा बनती है कि जवाबदेही की प्रक्रिया प्रभावी नहीं है।

यह कहना गलत होगा कि भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक सीमित है। भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या है, जो शासन के सभी अंगों गतिविधियों बच्चों को सकारात्मक संस्थाओं को प्रभावित करती है। फिर भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रभाव विशेष रूप से घातक होता है। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाए कि न्याय खरीदा या प्रभावित किया जा सकता है, तो कानून का शासन कमजोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न्याय पाने के लिए वैधानिक रास्तों के बजाय अन्य उपायों का सहारा

लेने लगते हैं, जिससे सामाजिक अस्थिरता और अराजकता बढ़ सकती है।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सामने एक और बड़ी चुनौती लंबित मामलों का भारी बोझ है। विभिन्न अदालतों में करोड़ों मामले वर्षों से लंबित हैं। न्यायाधीशों की कमी, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जटिल प्रक्रियाएं और बार-बार स्थगन, ये सभी कारण मिलकर समस्या को और गंभीर बनाते हैं। यद्यपि लंबित मामलों की अधिकता को सीधे भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता, लेकिन अत्यधिक विलंब से अनैतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलने की संभावना रहती है। जब न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं, तो कुछ लोग शॉर्टकट अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवस्था की कमजोरी और भ्रष्टाचार एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम से जुड़ा विवाद एक गहरे दार्शनिक प्रश्न को जन्म देता है, क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित कराया जाना चाहिए, या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखा जाना चाहिए? एक पक्ष यह मानता है कि कम उम्र में ऐसी जानकारी देने से संस्थाओं के प्रति सम्मान घट सकता है। दूसरा पक्ष कहता है कि लोकतंत्र में सजग और जागरूक नागरिक तैयार करना आवश्यक है। यदि बच्चों को संतुलित और तथ्यपूर्ण जानकारी दी जाए, जिसमें समस्याओं के साथ-साथ सुधार की प्रक्रियाओं और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो—तो यह शिक्षा नकारात्मकता नहीं, बल्कि जागरूकता पैदा करेगी। यह भी सच है कि भारतीय न्यायपालिका ने अनेक ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से साहस और स्वतंत्रता का परिचय दिया है। अदालतों ने मौलिक अधिकारों का विस्तार किया, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती दी, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया और कई संवेदनशील मामलों में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की। अनेक न्यायाधीशों ने निष्कलंक सेवा और उच्च नैतिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिए भ्रष्टाचार पर चर्चा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ आरोपों के आधार पर पूरी संस्था को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।

समय-समय पर न्यायिक सुधारों के प्रस्ताव भी सामने आते रहे हैं। इनमें एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र की स्थापना, संपत्ति की पारदर्शी घोषणा, आंतरिक आचार संहिता को सुदृढ़ करना, अदालतों का डिजिटलीकरण और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना शामिल हैं। ई-कोर्ट, वचुअल सुनवाई और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग जैसी तकनीकी पहलें पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं और अनियमितताओं की संभावनाओं को कम कर सकती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर भी बहस जारी है। किंतु हर सुधार में यह संतुलन बनाए रखना होगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित न हो, साथ ही जवाबदेही भी सुनिश्चित हो।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा संयमित, तथ्यों पर आधारित और सुधार की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। अतिरिक्त आरोप या राजनीतिक हमला संस्था को कमजोर कर सकते हैं, जबकि मौन या इनकार से समस्या गहरी हो सकती है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उन्हें सुधारने का साहस दिखाए। पाठ्यपुस्तक से जुड़े विवाद के मूल में यही द्वंद्व है, संस्था की प्रतिष्ठा बनाम पारदर्शिता। यदि शैक्षिक सामग्री से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो वास्तविकता नहीं बदलती। बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रस्तुत कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होगा चाहिए।

वास्तव में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि यह न्याय की नैतिक नींव को हिला सकता है। जवाबदेही की प्रक्रियाओं को मजबूत करना, लंबित मामलों को कम करना और न्यायाधीशों की कमी दूर करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे बढ़कर, जनता का विश्वास बनाए रखना ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से कमजोर नहीं होता; वह तब कमजोर होता है जब वह उन्हें छिपाने का प्रयास करता है। आगे का मार्ग छिपाने में नहीं, बल्कि सुधार और पारदर्शिता में निहित है।

बढ़ती आक्रामकता : युवाओं के मन का मौन संकट



हाल के वर्षों में बच्चों और युवाओं के बीच बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियाँ समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई हैं। आप दिन आक्रामक व्यवहार, मापीट, बुलिंग और यहाँ तक कि गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता को खबरें सामने आती हैं, जो पूरे समाज को झकझोर देती हैं। बच्चे और युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यदि उनकी ऊर्जा और क्षमता रचनात्मक दिशा में जाने के बजाय विनाशकारी रास्तों पर मुड़ने लगे, तो यह केवल व्यक्तिगत अचances नहीं, बल्कि परिवार, समाज और व्यवस्था की गहरी समस्या का संकेत है। आज जिस तरह आक्रामकता को सामान्य व्यवहार की तरह स्वीकार किया जाने लगा है, वह इस बात का प्रमाण है कि यह कोई एक-दो घटनाओं तक सीमित समस्या नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक चुनौती है, जिस पर गंभीरता से विचार और कार्य करने की आवश्यकता है। इस बढ़ती हिंसा के पीछे जिन कारणों पर सबसे अधिक चर्चा होती है, उनमें डिजिटल मीडिया का प्रभाव प्रमुख है। आज के बच्चे और किशोर ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे रहते हैं, जहाँ हिंसक दृश्य और आक्रामक व्यवहार को अक्सर मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कोमल और संवेदनशील मन बार-बार आक्रामकता और हिंसा से भरे दृश्य देखते हैं, तो धीरे-धीरे उनके मन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच का अंतर धुंधला पड़ने लगता है। लगातार ऐसे दृश्य देखने से संवेदनशीलता कम हो सकती है और हिंसा को लेकर मन की प्रतिक्रिया सुस्त पड़ जाती है। हालांकि हर हिंसक घटना के लिए केवल डिजिटल माध्यमों को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि इनका प्रभाव अचances के विचार,

भाषा और व्यवहार पर पड़ता है। यदि सही मार्गदर्शन औरसंतुलित निगरानी न हो, तो यह प्रभाव उनके व्यक्तित्व को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है।

परिवार का वातावरण भी बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर ही वह पहला स्थान है जहाँ बच्चा जीवन के मूल्यों, भावनात्मक व्यवहार और समस्याओं से निपटने के तरीकों को सीखता है। यदि घर का वातावरण तनावपूर्ण हो, माता-पिता के बीच निरंतर झगड़े होते हों, कठोर अनुशासन या उपेक्षा का माहौल हो, या नशे जैसी बुरी आदतें मौजूद हों, तो बच्चे के मन में असुरक्षा और आक्रोश पनप सकता है। जब उसकी भावनात्मक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं और उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता, तो भीतर जमा हुआ तनाव कभी-कभी आक्रामकता के रूप में बाहर आता है। अत्यधिक अपेक्षाएँ भी बच्चों पर मानसिक दबाव डालती हैं, विशेषकर पढ़ाई और करियर को लेकर। जब बच्चा स्वयं को समझा या स्वीकार किया हुआ महसूस नहीं करता, तो उसके भीतर असंतोष और विद्रोह की भावना जन्म ले सकती है। इसके विपरीत, यदि परिवार में संवाद, स्नेह और संतुलित अनुशासन का वातावरण हो, तो बच्चे के मन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना विकसित होती है, जो उसे हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रखती है।

साथियों का प्रभाव और आपसी तुलना भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति अपनी पहचान खोजता है और मित्रों से स्वीकृति पाना चाहता है। यदि किसी समूह में दर्बगई, डराना-धमकाना या जोखिमभरा व्यवहार लोकप्रियता का साधन बन जाए, तो कई किशोर उसी राह पर चलने लगते हैं। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और तेज कर देता है, क्योंकि वहाँ सफलता, सुंदरता और संपन्नता की चमकदार तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। इनसे तुलना करके कई युवा स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। यह हीनभावना कभी-कभी गुस्से और आक्रोश में बदल जाती है। कुछ युवा अपनी कमजोरी को छिपाने या निराकरण जताने के लिए आक्रामक व्यवहार का सहारा लेते हैं, जो धीरे-धीरे आदत बन सकता है। विद्यालय का वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास का केंद्र होता है। लेकिन जब कक्षाएँ भीड़भाड़ से भरी हों, प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हो और परामर्श सेवाएँ सीमित हों, तो छात्रों की मानसिक समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाता। बुलिंग, चाहे वह शारीरिक हो या ऑनलाइन, आज एक गंभीर समस्या है। बुलिंग का शिकार होने वाले बच्चे चिंता, अवसाद और क्रोध से गुजरते हैं, जबकि ऐसा करने वाले बच्चे भी अक्सर किसी आंतरिक पीड़ा या असुरक्षा से जूझ रहे होते हैं। यदि समय रहते हस्तक्षेप न किया जाए, तो यह चक्र और अधिक खतरनाक रूप ले सकता है। इसलिए स्कूलों में सुदृढ़ परामर्श व्यवस्था, स्पष्ट नियम और संवेदनशील वातावरण की आवश्यकता है, जहाँ हर बच्चा सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी युवाओं के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता और अपराध से घिरे वातावरण में पलने वाले बच्चों पर निरंतर तनाव बना रहता है। जब उन्हें आगे बढ़ने के अवसर सीमित दिखाई देते हैं, तो उनके मन में निराशा और हताशा जन्म ले सकती है। समाज में शक्ति और बदले की भावना को महिमा मंडित करने वाली सोच भी हिंसा को एक वैध साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। ऐसे में केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुधार पर्याप्त नहीं होता; व्यापक सामाजिक बदलाव भी आवश्यक होते हैं, जो समान अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करें।

बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। चिंता, अवसाद, ध्यान की समस्या या किसी आघात का असर यदि समय पर समझा और संभाला न जाए, तो वह चिड़चिड़ापन और आक्रामकता में बदल सकता है। दुर्भाग्य से कई स्थानों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं या उनके प्रति सामाजिक झिझक बनी रहती है। कई बार माता-पिता या शिक्षक बच्चे की परेशानी को अनुशासनहीनता समझ लेते हैं और दंड का सहारा लेते हैं, जबकि उसे समझ और सहारे की आवश्यकता होती है। यदि समय रहते पहचान औरपरामर्श मिल जाए, तो

स्थिति को सुधारा जा सकता है। फिर भी यह याद रखना आवश्यक है कि युवावस्था ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्साह का समय है। सही दिशा और मार्गदर्शन मिलने पर यही ऊर्जा समाज के निर्माण में लगा सकती है। खेल, कला, संगीत, पठन-पाठन और सामाजिक सेवा जैसी गतिविधियाँ बच्चों को सकारात्मक मंच देती हैं, जहाँ वे अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। परिवार में खुला संवाद, जहाँ बच्चा बिना डर अपनी बात कह सके, हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने का प्रभावी उपाय है।

डिजिटल साक्षरता भी अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे मीडिया सामग्री को समझदारी से देखें और सही-गलत का विवेक विकसित करें। स्क्रीन समय पर संतुलित नियंत्रण और माता-पिता की सहभागिता विश्वास और समझ को मजबूत करती है। स्कूलों में भावनात्मक संतुलन, संवाद कौशल और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे आधुनिक चुनौतियों का सामना संयम से कर सकें।

बच्चों और युवाओं में बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियाँ कई कारणों के मेल से उत्पन्न होती हैं, व्यक्तिगत, परिवारिक, सामाजिक और तकनीकी सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। केवल दंड या आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। परिवार संवाद और स्नेह को प्राथमिकता दें, स्कूल भावनात्मक विकास को महत्व दें, समाज सुरक्षित और समान अवसर प्रदान करें, और नीतियाँ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। यदि हम मिलकर बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तो यह चुनौती एक अवसर में बदल सकती है। बच्चों का संवेदनशील और संतुलित विकास केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक अधिक शांत, सुरक्षित और सहृदय दुनिया का निर्माण कर सके।

जीवन भी एक रेलयात्रा है



अनुभव
- वृजेश प्रसाद

लंबे समय बाद अपने गाँव की ओर यात्रा करने का अवसर मिला। अक्सर था-शारी-ब्याह और होली का मौसम। स्वाभाविक था कि रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई थी। ट्रेन कोलकाता से खुली और कुछ ही समय बाद अगले स्टेशन पर पहुँचते-पहुँचते भीड़ का सैलाब डिब्बों में उमड़ पड़ा। लोग उत्साह, जल्दबाजी और थोड़ी-सी अधीरता के साथ डिब्बों में चढ़ रहे थे। किसी को खिड़की की सीट चाहिए थी, किसी को ऊपर की बर्थें। सीटों को लेकर झिझक, आग्रह और कहीं-कहीं हल्की नोकझोंक-मानो पूरी ट्रेन पर उसी आ अधिकार हो। जिन यात्रियों के पास आरएसी टिकट थी, उनका हाल और भी दयनीय था। वे आधी सीट पर सिमटे हुए, अपने हिस्से के स्थान को बचाए रखने की चेष्टा कर रहे थे।

कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा-सामान रखने की जगह को लेकर तर्क-वितर्क, सीट के अधिकार को लेकर बहस। प्रत्येक व्यक्ति अपने छेटे-से दायरे को सुरक्षित रखने में लगा था। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता था मानो यह स्थान स्थायी हो, मानो यही जीवन का अंतिम पड़ाव हो।

परंतु समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे-धीरे ट्रेन अपने आधे सफर को पार कर चुकी थी। अब वही

यात्री, जो थोड़ी देर पहले अधिकार के लिए व्याकुल थे, शांत होकर बैठ गए थे। किसी ने बिस्तर समेटा, किसी ने थैला व्यवस्थित किया, कोई अपने गंतव्य के आने की प्रतीक्षा में खिड़की से बाहर देखने लगा।

एक-एक कर यात्री उतरते गए। डिब्बा धीरे-धीरे खाली होने लगा। जिन सीटों के लिए कुछ घंटे पहले विवाद हुआ था, वे अब निःशब्द और रिक्त पड़ी थीं-मानो कभी किसी ने उन पर अपना अधिकार जताया ही न हो।

इस दृश्य ने मन में एक गहरी अनुभूति जगाई-क्या जीवन भी ऐसी ही एक रेलयात्रा नहीं है?

यौवन के प्रारंभिक दिनों में हम 'मेरा' और 'तेरा' के भेद में उलझे रहते हैं। घर, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति-इन सब पर अपना अधिकार स्थापित करने की होड़ लगी रहती है। हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं, स्वामी नहीं। यह यात्रा अस्थायी है और हर स्टेशन पर कोई-न-कोई उतरने वाला है। समय की रेलगाड़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है। धीरे-धीरे हम भी अपने अनुभवों को समेटते हैं, अपने मोह को सहजते हैं और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर अपनी अंतिम मंजिल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पीछे रह जाती है वे खाली सीटें, जो कभी हमारे अधिकार और अहंकार का प्रतीक थीं।

जीवन का सत्य सरल है-यह एक यात्रा है, पड़ाव नहीं। जो आज हमारा है, वह कल किसी और का होगा। इसलिए अधिकार से अधिक आवश्यक है-सहयात्रियों के प्रति सहनशुभ्रति, और यात्रा के प्रति विनम्रता।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विवाद लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

समर्थन नगद हो या विरोध, बात टाइमिंग की है



तीते दिनों राजधानी में आयोजित 'इंडिया एआई इपैक्ट समिट' में ग्लोबोटिया यूनिवर्सिटी की मैडम साहिबा ने जाने या अनजाने में चीनी रोबोट डॉग को अपना बता दिया गया। पृष्ठों पर सफाई भी दे डाली। एक बार तो लगा क्या हुआ जब ड्रेगन हमारी जमीन को अपना बता सकता है तो हम उसके आर्टिफिशियल डॉग को भी अपना नहीं बता सकते क्या? खैर...इस घटना से दुनिया में देश की छवि खराब होने से भयंकर आहत युवा कांग्रेसियों द्वारा किया गया शर्टलेस विरोध प्रदर्शन इन दिनों खासा चर्चा में

है। यत्र-तत्र सर्वत्र उनके इस कृत्य की घनघोर निंदा हो रही है।

आज देश दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी-वैसी बात होने पर सर्वाधिक आहत नेता ही होते हैं। नेताओं के पीछे पहले से आहत पब्लिक आहत हो जाए ये अलग बात है। भाजपाई कह रहे इनकी इस टाइप की हरकत से दुनिया में देश की छवि खराब हुई। इन्हें प्रदर्शन करना ही था तो समिट साइट से कहीं दूर जाकर एकांत में या जंतर-मंतर,इंडिया गेट...पर जाकर कर लेते,जो प्रायः प्रदर्शन करने के लिए ही जानी जाती है। दूसरी ओर कांग्रेस हार्दिकमान का मानना है कि उनके बब्वर शेरों ने शर्ट उतारकर जो किया बिल्कुल सही किया,सही के सिवा कुछ न किया। दलों के दावे जो भी हो आम नागरिक समझ नहीं पा रहा कि देश की छवि

दीगर डॉग के प्रदर्शन से खराब हुई या देशभक्ति में शर्ट उतारने वालों से



एकचुअली विरोध ऐसा कृत्य है जो प्रदर्शन के लिए ही किया जाता है क्योंकि विरोध है भाई साहब कोई

दान-धर्म तो नहीं जो दाएं हाथ से करो और बायां बेखबर रहे। इधर तो

किया जा सकता है लेकिन विरोध के चोखना-चिल्लाना,तोड़-फोड़ करना, सार्वजनिक की जगह को लेकर जलना जरूरी सा हो जाता है। कभी लोग चक्का जाम कर,काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करवाते थे। धीरे-धीरे बांध पर काली पट्टी बांध अपना विरोध जताने लगे,फिर कपड़े फाड़ने लगे अब अर्द्धनग्न होकर विरोध किया जाने लगा है। इसे प्रदर्शन करने वालों की समझदारी ही कहेंगे कि वे सिरिप आधे कपड़े उतार रहे हैं अब्बल तो यह कि बिचारे दूसरों के कपड़े उतारने के बरअक्स खुद के कपड़े उतार रहे हैं।

एक बात समझ लीजिए 'लोकतंत्र समर्थन से जन्मता है लेकिन विरोध से जिंदा रहता है।' इसमें सबको विरोध करने का

अधिकार है बस टाइमिंग जरूरी है। समर्थन और विरोध की टाइमिंग के दो श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत और रामायण में देखने को मिलते हैं। महाभारत में द्रोपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे दिग्गजों का मौन धारण करना दुःशासन और दुर्गोधन के पक्ष में अप्रत्यक्ष समर्थन था। गर वे मौके पर विरोध कर देते तो कदाचित महाभारत नहीं होता। उधर रामायण में भी श्रीराम के राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेई का हेमपीलेस होकर कोप भवन में जाना विरोध की राइट च्वाइस टाइमिंग थी। काश! कैकेई श्रीराम के राज्याभिषेक का समर्थन कर देती तो श्रीराम न तो चौदह वरस का वनवास झेलते न रामायण बनती।

बहरहाल,कार्य कर्ता हुआ करता कि आया काम बस निर्विघ्न निपट जाए मगर विरोध करने वाला चाहता है यही वक्त है पूर कर ले आहजू...!

वक्रोचित

चंद्रशेखर साकल्ले

लेखक मग्न जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।



कवि सम्मेलनों का स्वर्णिम दौर गुजर चुका था। हर कस्बे और शहर में साल में चार बार होने वाले कवि सम्मेलन अब अतीत बन चुके थे। कविगण उसके अवसान से अवसाद में थे। वे बड़ी शिद्दत से उन दिनों को याद कर रहे थे, जब वो कलफ लगे कुर्ते पर जाकिट पहन कर बड़ी शान से मंच पर चढ़ते थे। उनके गीतों की एक-एक पंक्ति पर तालियाँ बजती थीं। कुछ अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों की शोभा बढ़ाते थे। कुछ का दायरा आसपास के शहरों और कस्बों तक सीमित था और कुछ स्थानीय कवि सम्मेलनों में स्थानीय कवि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे।

पहले तो कवियों को विश्वास नहीं हुआ कि कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगा आयोजक षड्यंत्र पूर्वक उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को फोन लगाया। आयोजकों ने कहा कि अब कविताएं धूल भरे मैदानों में अस्थायी मंच बनाकर आम आदमी को नहीं सुनाई जातीं। अब कविताएं जमीन पर बैठ कर भी नहीं सुनी जातीं। वहाँ पान और गुटखे नहीं होते। न ही बीड़ी सिगरेट का धुआँ होता है। कवियों को हूट भी नहीं किया जाता। अब कविताएं न्यूज चैनलों के साहित्यिक कार्यक्रमों और लिटफेस्ट में सजे-धजे हॉल में शांत वातावरण में सुनाई जाती हैं। यहाँ आमंत्रित श्रोता कुर्सियों पर बैठ कर कविता सुनते हैं। कविता सुनाने वाले भी बसों में धक्के खाते नहीं आते। हवाई जहाज से आते हैं। जब से आभिजात्य वर्ग में साहित्य फैशन बना है, कवि भी सेलिब्रिटी हो गए हैं। अंत में आयोजकों ने हाथ जोड़कर कहा 'भैया, हम मध्यम श्रेणी के आयोजक हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम आपको वहाँ एंटी कर सकें।

आयोजकों से निराश कवियों ने कवि गोष्ठियों से काम चलाना चाहा पर, समस्या आयोजक और आयोजन-स्थल की थी। तभी एक ऐसा समाचार आया कि कवि गोष्ठी करना अनिवार्य हो गया। हुआ यह कि केंद्र सरकार के रेल बजट में घोषणा की गई कि उनके कस्बे को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। यानि अब उनकेकस्बे में भी रेल आएगी। कस्बे की बड़ी पुरानी मांग

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।



विज्ञान मानव को जीवन जीने की एक दृष्टि देता है। चिंतन की आधारभूमि भेंट कर चलने को उजास भरा पथ प्रदान करता है। वास्तव में विज्ञान जीवन से जड़ता, अविद्या, अंधविश्वास, अतार्किकता एवं संशय से मुक्ति का नाम है। विज्ञान व्यक्ति को तर्कशील एवं प्रयोगधर्मी बनाकर सवाल खड़े करने की सामर्थ्य पैदा करता है। विज्ञान मानवीय मेधा का उच्चतम आदर्श है। वसुधा के सौंदर्य को अधुष्ण बनाये रखते हुए प्राणिमात्र के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपभोग का मार्गदर्शन ही विज्ञान है। विज्ञान में समस्या है तो समाधान भी, कल्पना है तो प्रयोग भी। सवाल हैं तो उत्तरों की तह तक पहुँच सत्य का साक्षात्कार करने का सत्संकल्प भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से हम इस भाव एवं चेतना को सिंचित कर समृद्ध करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा युवाओं एवं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1986 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 1928 को ही सी.वी. रमन ने लोक सम्मुख अपनी विश्व प्रसिद्ध खोज 'रमन प्रभाव' की घोषणा की थी। 'रमन प्रभाव' के लिए ही 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सी.वी. रमन एशिया के पहले भौतिक शास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने 1998 में 'रमन प्रभाव' को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के

विकास और कर्ज

कृष्णार्जुन बर्व

लेखक अजीविका मिशन से जुड़े हुए हैं।



हम सब लाडली बहन योजना को भली-भाँति जानते हैं। प्रदेश में 'लाडली बहना योजना' के माध्यम से लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह रू. 1,500 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है। निस्संदेह, जब रू. 1,500 प्रतिमाह सीधे महिला के खाते में आते हैं तो उसकी आर्थिक पहचान मजबूत होती है, परिवार में उसकी बात कुछ अधिक सुनी जाती है और बैंकिंग व्यवस्था से उसका जुड़ाव बढ़ता है। परंतु क्या केवल रू. 1,500 की मासिक सहायता ही सशक्तिकरण की परिभाषा है? क्या आर्थिक आत्मनिर्भरता का अर्थ नियमित रोजगार, कौशल विकास और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा नहीं होना चाहिए? यदि सशक्तिकरण का अर्थ केवल नकद हस्तांतरण तक सीमित रह जाए, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हम महिलाओं को वास्तव में सक्षम बना रहे हैं – या उन्हें सीमित आर्थिक सहाय देकर संतुष्ट मान रहे हैं? कागजों और घोषणाओं में योजनाएँ भले ही सशक्तिकरण का बड़ा चित्र प्रस्तुत करती हों, पर जमीन स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक दिखाई देते हैं। पेंशन प्रणाली के अभाव में लाभार्थियों को समाज पर राशि नहीं मिलती, बैंकिंग प्रक्रियाओं में तकनीकी अडचनें आती हैं, और पात्रता सत्यापन की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं।

लिटफेस्ट, कवि गोष्ठी और रेल के आने का फिरसा

पहले तो कवियों को विश्वास नहीं हुआ कि कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। उन्हें लगा आयोजक षड्यंत्र पूर्वक उन्हें आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आयोजकों को फोन लगाया। आयोजकों ने कहा कि अब कविताएं धूल भरे मैदानों में अस्थायी मंच बनाकर आम आदमी को नहीं सुनाई जातीं। अब कविताएं जमीन पर बैठ कर भी नहीं सुनी जातीं। वहाँ पान और गुटखे नहीं होते। न ही बीड़ी सिगरेट का धुआँ होता है। कवियों को हूट भी नहीं किया जाता। अब कविताएं न्यूज चैनलों के साहित्यिक कार्यक्रमों और लिटफेस्ट में सजे-धजे हॉल में शांत वातावरण में सुनाई जाती हैं। यहाँ आमंत्रित श्रोता कुर्सियों पर बैठ कर कविता सुनते हैं। कविता सुनाने वाले भी बसों में धक्के खाते नहीं आते। हवाई जहाज से आते हैं। जब से आभिजात्य वर्ग में साहित्य फैशन बना है, कवि भी सेलिब्रिटी हो गए हैं।

स्वीकृत हुई। पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। इस शुभ अवसर पर कवियों ने भी तय किया कि कस्बे में रेल आने की खुशी में एक कवि गोष्ठी की जाए। गोष्ठी में सिर्फ रेल से संबंधित कविताएँ पढ़ी जाएंगी।बस, फिर क्या था, गीत अंकुरित होने लगे। दोहों की फसल लहलहाते लगी। छंद पके फलों की तरह टप-टप कर गिरने लगे। सारे कवियों ने रेल पर कविताएँ लिखा डालीं। यक्ष प्रश्न यह था कि कवि गोष्ठी कहाँ आयोजित की जाए।

सबकी निगाहें बलभद्र जी पर गईं। बलभद्र जी हेड कास्टेबल से रिटायर हुए थे, पर कस्बे में एस पी साहब के नाम से सम्मानित थे। उनका कस्बे से सटा एक फार्महाउस था। वहाँ वे सब्जियाँ उगाते थे और गायें पालते थे। फार्महाउस में उनका बड़ा -सा बंगला था,जिसमें वे रहते थे। बलभद्र जी संगीत प्रेमी थे, संगीत की महफिलें सजाते थे। बंगले में एक बड़ा हॉल था जिसमें म्यूजिक सिस्टम था, गद्दे बिछे थे और गाव तकिये लगे थे। अफवाह थी कि यहाँ गाने के साथ नाच भी होता था, पर किसी ने देखा नहीं था।

बलभद्र जी ने कवियों का अनुरोध सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कवियों के सम्मान में समोसे और जलेबी भी बुलवा लिए,जो चाय औरबिस्कुट के अलावा थे। बलभद्र जी ने कवियों के सामने एक छोटी-सी शर्त रखी कि वे भी अपने कुछ गीत सुनाएँ,जिसे कवियों ने तुरंत मान लिया।

कवि गोष्ठी के दिन कवियों को अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने कुर्ते धुलवाए, उनमें कलफ लगवाया, जाकिट पहनी और कविताएँ लेकर फार्म हाउस पहुँच गए। सबसे पहले बलभद्र जी ने एक फिल्मी गीत सुनाया। 'शमा है शुहाना शुहाना' फिर एक गैर फिल्मी गीत गाया। जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह राग पहाड़ी पर आधारित है। इसके बाद श्रीमती बलभद्र ने

हारमोनियम पर दो लोकगीत गाए। फिर कवियों का नंबर आया, जो अब तक बेचैन हो चुके थे। सबसे पहले श्रीमती 'कृष्णदासी'जी ने एक स्वागत गीत गाया।

'मैं तो बारी जाऊँ रे रेल तेरी सीटी पे' इसकी धुन संतोषी माता की आरती से काफी मिलती-जुलती थी। बाल कविताओं के गीतकार 'भोलामन'जी ने एक बालगीत सुनाया।

'मोटी सीटी बजाती रेल आई बच्चों को नानी घर लाई'

लोकगीतों के गायक 'सावन'जी ने स्वरचित गीत गाया।

'जैसे मिल गई हो खोई हुई मुंदरी ऐसे आई हो तुम ओ रेल सुंदरी।'

मुक्त छंद के सशक्त हस्ताक्षर 'प्रहरी'जी ने कविता पढ़ी।

'जैसे स्वागत करता है किसान आषाढ़ के बादल का जैसे स्वागत करता है प्रेमी प्रेमिका के कदमों की आहट का जैसे स्वागत करता है सरकारी कर्मचारी पहली तारीख का आओ रेल मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ।'

कविता को भरपूर दाद मिली।

प्रेम कविताओं के लिए प्रसिद्ध 'दीवाना'जी ने अपनी प्रेमिका पर पांच सौ से ज्यादा कविताएँ लिखी थीं। वे सिर्फ प्रेम कविताएँ लिखते थे। उन्होंनेअपनी प्रेमिका का सम्पूर्ण नख-शिख वर्णन अपनी कविताओं में कर दिया था।वे अपनी प्रेमिका की जुल्फों के साये में सोते थे और उसकी पायल की छन-छन पर मयूर की तरह नाचते थे।

उसके रूप पर हजार बार मर चुके थे, वैसे भौतिक रूप से जिंदा और स्वस्थ थे। उन्होंने पहली बार प्रेमिका से हट कर रेल पर कविता लिखी। हालांकि रूपक प्रेम का ही चुनाव।

'अश्रुजल से पथ सींचू पलकों से तेरी राह बुहाऊँ तुम आ रही हो जिस ओर से उस दिशा की आरती उतारूँ।

इस पर बहुत देर तक तालियाँ बजती रहीं।इसके बाद

'घायल'जी का नंबर आया।'घायल'जी के बाद 'पायल' जी को कविता पढ़नी थी। 'घायल' जी और 'पायल' जी को आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक-दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे।'घायल'जी 'पायल'जी को दो कौड़ी का कवि मानते थे, जबकि 'पायल' जी 'घायल'जी को कवि ही नहीं मानते थे। 'घायल' जी स्थानीय कवि सम्मेलनों में मंच संचालक से सांठांट कर 'पायल'जी को वरिष्ठकवि घोषित कर अध्यक्ष बनवा देते थे और इस तरह कविता पढ़ने से वंचित करदेते थे।'पायल'जी भी कम नहीं थे। उन्होंने 'घायल'जीके प्रथम पुष्प यानीपहले कविता संग्रह के विमोचन के दिन अपने एक व्यवसायी मित्र से कह कर पासके कस्बे में कवि सम्मेलन रखवा दिया और कवियों के आने-जाने के लिए बस की व्यवस्था करवा दी।'घायल'जी ने विमोचन कार्यक्रम की भारी भरकम तैयारी की थी, पर उसमें गिनती के लोग ही पहुँचे थे। दोनों एक- दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। बहहहाल....'घायल'जी ने कविता पढ़ना शुरू किया।

'सिंगपिंग करती रेल आई सिंगपिंग करती रेल आई'

'पायल'जी ने तुरंत हस्तक्षेप किया

'रेल तो छुक-छुक करती आती है,ये सिंगपिंग क्या है?'

'घायल'जी ने कहा 'ये काव्यात्मक प्रयोग है। 'पायल'जी-प्रयोग तो है, पर एकदम बेतुका प्रयोग है।' 'घायल'जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा 'इसमें अलंकार देखिए।'

'पायल'जी जरा जोर से बोले 'मुझे तो कोई अलंकार नहीं दिख रहा है। बताइए कौन -सा अलंकार है?'

'घायल'जी बात संभालते हुए बोले 'इसमें एक लय है।'

'पायल' जी और जोर से बोले 'लय को क्या चाटें,लय में तो कुत्ता भी भौंकता है तो क्या उसे भी कवि मान लें।'

इतना सुनना था कि 'घायल'जी का पारा आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने 'पायल'जी का कुर्ता पकड़ा और खींचा।'पायल'जी ने उस कुर्ते कोपहनकर बड़े -बड़े कवि सम्मेलनों में भाग लिया था। कुर्ता चर्र से फटगया।'पायल'जी ने

'घायल'जी को धक्का दिया।'घायल'जी गिर गए। दोनों मेंहाथापाई होने लगी। देखते -देखते कवि गोष्ठी कुश्ती के अखाड़े में बदल गई। कुछ कवि 'घायल'जी के पक्ष में खड़े हो गए। कुछ 'पायल'जी के साथ हो गए।सारे कवि गुथमगुथा होने लगे।तभी बलभद्र जी की जोरदार आवाज गूँजी 'बंद करो ये सब, करना गोली मार दूँगा। 'कवियों ने देखा सचमुच बलभद्र जी अपनी दुनाली लिए खड़े थे।कवियों ने लड़ाई बंद की। बलभद्र जी फिर गरजे 'भागो यहाँ से, आईंदा से कोई भी कवि मेरे पास आया तो गोली मार दूँगा। 'खबराए कवि बाहर भागे।

इसके बाद कस्बे में कवि गोष्ठी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद सारे कवि फेंसबुक में समा गए।अब वे रोज एक कविता पोस्ट करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और रात को लाइक्स गिनकर सो जाते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

प्रमोद दीक्षित मलय

लेखक शिक्षक एवं शैक्षिक संवाद मंच के संस्थापक हैं।



विज्ञान मानव को जीवन जीने की एक दृष्टि देता है। चिंतन की आधारभूमि भेंट कर चलने को उजास भरा पथ प्रदान करता है। वास्तव में विज्ञान जीवन से जड़ता, अविद्या, अंधविश्वास, अतार्किकता एवं संशय से मुक्ति का नाम है। विज्ञान व्यक्ति को तर्कशील एवं प्रयोगधर्मी बनाकर सवाल खड़े करने की सामर्थ्य पैदा करता है। विज्ञान मानवीय मेधा का उच्चतम आदर्श है। वसुधा के सौंदर्य को अधुष्ण बनाये रखते हुए प्राणिमात्र के लिए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपभोग का मार्गदर्शन ही विज्ञान है। विज्ञान में समस्या है तो समाधान भी, कल्पना है तो प्रयोग भी। सवाल हैं तो उत्तरों की तह तक पहुँच सत्य का साक्षात्कार करने का सत्संकल्प भी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के माध्यम से हम इस भाव एवं चेतना को सिंचित कर समृद्ध करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा युवाओं एवं बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विज्ञान अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1986 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 1928 को ही सी.वी. रमन ने लोक सम्मुख अपनी विश्व प्रसिद्ध खोज 'रमन प्रभाव' की घोषणा की थी। 'रमन प्रभाव' के लिए ही 1930 में सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सी.वी. रमन एशिया के पहले भौतिक शास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। अमेरिकन केमिकल सोसायटी ने 1998 में 'रमन प्रभाव' को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान के

जीवन में वैज्ञानिक विवेक एवं दृष्टिकोण आवश्यक

इतिहास की एक युगान्तरकारी घटना के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वास्तव में 'रमन प्रभाव' के स्मरण के साथ ही मानव जीवन के सम्यक विकास के लिए वैज्ञानिक विवेक, चिंतन एवं दृष्टिकोण अपनाने का दिन है, जिसकी हमें जरूरत है।

चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवम्बर, 1888 को तमिलनाडु में कावेरी के तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपकी माता पार्वती अम्मा कुशल गृहिणी एवं पिता चन्द्रशेखर भौतिक शास्त्र एवं गणित के प्राध्यापक थे। घर पर एक समृद्ध लघु पुस्तकालय था तो तार वाद्ययंत्रों का संचय भी। संगीत में रुचि के चलते वीणा वादन पिता जी की नित्य साधना थी। वीणा के तारों के कम्पन से निकली मधुर ध्वनि बालक रमन को अपनी ओर खींचती। वह सोचते कि इन तारों को छेड़ने से एक विशेष लय, प्रवाह, आरोह-अवरोह में मनमोहक ध्वनि कैसे उत्पन्न हो सकती है। यही जिज्ञासा बाद में उनके ध्वनि सम्बंधी शोधों का आधार भी बनी। चार वर्ष की उम्र में ही पिता का तबादला विशाखापट्टनम हो जाने से रमन की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शुरू हुई। यहां घर के सामने लहराता सागर का नीला जल रमन का ध्यान आकर्षित करता। बालमन सोचता कि घर और सागर के जल में यह

अन्तर कैसे। मकान की खिड़की से वह सागर की लहरों को अटखेलियाँ करते देखते रहते मानो जल के नीलेपन के रहस्य का कोई तोड़ खोज रहे हों। रमन ने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में 1903 में बी.ए. में प्रवेश लिया और विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में



प्रथम आकर गौरव अर्जित किया। 1907 में एम.ए. गणित प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया। परास्नातक करते समय ही 1906 में 'प्रकाश विवर्तन' विषय पर शोध पत्र लिखा जो लंदन से प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध पत्रिका 'फिलसोफिकल मैगजीन' में छपा। 1907 में ही आपने असिस्टेंट एकाउंटेंट जनरल के रूप में कलकत्ता में कार्यभार

ग्रहण किया। पर रमन का मन तो विज्ञान की दुनिया में ही रमा था। फलतः एक दिन कार्यालय से घर आते समय वर्ष 1876 में स्थापित 'इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस' की प्रयोगशाला में सुबह-शाम चार-चार घंटे 'ध्वनि मेंकम्पन एवं कार्य' के क्षेत्र में प्रयोग करने लगे। वह स्कूली बच्चों को प्रयोगशाला लाकर विज्ञान के विभिन्न प्रयोग करके दिखाते ताकि बच्चेविज्ञान की दुनिया को करीब से देख-परख सकें।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी के कहने पर 1917 में आपने नौकरी से त्यागपत्र देकर भौतिकी का प्राध्यापक बनना स्वीकार कर लिया। 1921 में ब्रिटेन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के काँग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु ऑक्सफोर्ड जाया हुआ। लौटते समय भूमध्य सागर के जल का नीलापन देखकर आप आश्चर्यचकित रह गए। विचार किया कि समुद्र के जल में नीलापन किस कारण से है। उपकरण लेकर आप जहाज के डेक पर आ गये और घंटों सिन्धु जल का अवलोकन-निरीक्षण और प्रयोग करते रहे। इस दौरान पूर्व में विज्ञानवेत्ताओं द्वारा खोजे गये सिद्धांत और निष्कर्ष आंखों के सामने घूमते रहे कि जल का नीलापन समुद्र के अन्दर से प्रकट हो रहा है। पर आप उनसे सहमत नहीं हो पा रहे

थे। तब रमनने इस रहस्य की खोज करने का संकल्प लिया और भारत आकर आपने प्रयोगशाला में 1921 से 1927 तक शोध किया जिसकी परिणति 'रमन प्रभाव' के रूप में हुई। 'रमन प्रभाव' प्रकाश का विभिन्न माध्यमों से गुजरने पर उसमें होने वाले भिन्न-भिन्न प्रकीर्णन के कारणों का अध्ययन है। सात साल की साधना का फल 'रमन प्रभाव' पर आधारित शोध पत्र 'नेचर' पत्रिका में सर्वप्रथम छपा था। 1924 में आपको रॉयल सोसायटी ऑफ लंदन का फेलो बनाया गया। 1927 में जर्मनी ने जर्मन भाषा में भौतिकशास्त्र का बीस खंडों का एक विश्वकोश प्रकाशितकिया। इसमें वाद्य यंत्रों से सम्बंधित आठवें खंड का लेखन रमन द्वारा किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इस विश्वकोश को तैयार करने वाले आप एकमात्र गैर जर्मन व्यक्ति थे। उनके 2000 शोध पत्र विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए। 1948 में आपने सेवानिवृत्ति के बाद बंगलुरु में 'रमन शोध संस्थान' की स्थापना की।

भारत सरकार ने 1954 में महान कर्मयोगी विज्ञानी रमन के योगदान और वैज्ञानिक उपलब्धियों का वंदन करते हुए 'भारत रत्न' पुरस्कार प्रदान किया। रूस ने 1957 में 'लेनिन शान्ति पुरस्कार' भेंटकर सम्मानित किया। संचार मंत्रालय ने 20 पैसे का एक टिकट जारी कर आपकी स्मृति को अधुष्ण बना दिया। विश्व का यह महान भौतिकविद् 21 नवम्बर, 1970 को अपना लौकिक जीवन पूर्ण कर हमें अकेला छोड़ अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर गया। लेकिन जब तक दुनिया में भौतिकी का अध्ययन होता रहेगा, तब तक 'रमन प्रभाव' अमर रहेगा और चन्द्रशेखर वेंकट रमन भी कोटि उरों में जीवित एवं श्रद्धास्पद बने रहेंगे।

क्या अंतिम व्यक्ति केंद्र में है?

औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों श्रमिक – विशेषकर छोटे एवं मध्यम कारखानों में काम करने वाले – नियमित सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। अनेक श्रमिकों को न तो भविष्य निधि (PF) की निरंतर सुविधा मिलती है, न ही ईएसआई (ESI) का समुचित लाभ। अस्थायी अनुबंध, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान और अनिश्चित रोजगार की स्थिति आज भी आम है। जब ये श्रमिक वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, तो उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। ऐसे में सीमित पेंशन और बढ़ती महंगाई का दोहरा दबाव उनकी स्थिति को और कठिन बना देता है। आज कई योजनाएँ 'गरीबों के लिए' घोषित की जाती हैं, पर उनका स्वरूप अक्सर 'गरीबों जैसी योजना' बनकर रह जाता है। सहायता की राशि इतनी सीमित होती है कि वह सम्मानजनक जीवन का आधार नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक सहायता बनती है। यदि योजनाएँ सचमुच गरीबों के लिए हैं, तो उन्हें गरीबों जैसी नहीं, बल्कि महंगाई के अनुरूप और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाली योजनाएँ होना चाहिए – जहाँ सहायता नहीं, अवसर और सुरक्षा केंद्र में हों।

दूसरी ओर, वृद्धा और विधवा पेंशन आज भी लगभग रू. 600 प्रतिमाह तक सीमित है। यह राशि वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है। 60 वर्ष से अधिक आयु की वे महिलाएँ, जो केवल पेंशन पर निर्भर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखा जाए। खुदरा महंगाई दर भले ही कुछ महीनों में नियंत्रित दिखाई दे, पर खाद्य पदार्थों, दाल, तेल, दूध, रसोई गैस, दवाइयों और परिवहन की लागत में लगातार उतार-चढ़ाव आम परिवार की जेब पर सीधा असर डालता है। निम्न आय वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। जब आय स्थिर रहे और खर्च बढ़ता जाए, तो वास्तविक आय घटती जाती है। रू. 600 की पेंशन आज उतनी वस्तुएँ नहीं खरीद सकती, जितनी कुछ वर्ष पहले खरीद पाती थी। यही स्थिति रू. 1,500 की सहायता राशि पर भी लागू होती है – महंगाई के साथ उसकी वास्तविक क्रय शक्ति

धीरे-धीरे कम होती जाती है। इसी संदर्भ में प्रदेश के असंगठित कारखाना श्रमिकों की स्थिति और भी गंभीर है। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत हजारों श्रमिक – विशेषकर छोटे एवं मध्यम कारखानों में काम करने वाले – नियमित सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। अनेक श्रमिकों को न तो भविष्य निधि (PF) की निरंतर सुविधा मिलती है, न ही ईएसआई (ESI) का समुचित लाभ। अस्थायी अनुबंध, न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान और अनिश्चित रोजगार की स्थिति आज भी आम है। जब ये श्रमिक वृद्धावस्था में पहुँचते हैं, तो उनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता। ऐसे में सीमित पेंशन और बढ़ती महंगाई का दोहरा दबाव उनकी स्थिति को और कठिन बना देता है।

आज कई योजनाएँ 'गरीबों के लिए' घोषित की जाती हैं, पर उनका स्वरूप अक्सर 'गरीबों जैसी योजना' बनकर रह जाता है। सहायता की राशि इतनी सीमित होती है कि वह सम्मानजनक जीवन

का आधार नहीं, बल्कि केवल प्रतीकात्मक सहायता बनती है। यदि योजनाएँ सचमुच गरीबों के लिए हैं, तो उन्हें गरीबों जैसी नहीं, बल्कि महंगाई के अनुरूप और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने वाली योजनाएँ होना चाहिए – जहाँ सहायता नहीं, अवसर और सुरक्षा केंद्र में हों। साथ ही यह भी आवश्यक है कि चुनाव पूर्व प्रारंभ की गई योजना में निर्धारित पात्रता का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव सत्यापन हुआ। आय सीमा, आय सीमा, आधार-समग्र लिंकिंग और बैंक खाते की शर्तें तय की गईं, परंतु अल्प समय में हुए बड़े पैमाने के पंजीयन के बाद लाभार्थी सूची के स्वतंत्र ऑडिट और निरंतर समीक्षा की आवश्यकता स्वाभाविक है।

इधर, मध्यप्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 67,300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण ले चुकी है। हाल ही में 5,300 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण भी उठाया गया। राज्यों के लिए ऋण लेना असामान्य

नहीं है – अधोसंरचना, उद्योग, वेतन-भुगतान और पूंजीगत निवेश के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। परंतु जब इतनी बड़ी उधारी के समानांतर सामाजिक सुरक्षा की वास्तविक स्थिति और महंगाई के प्रभाव पर दृष्टि डालते हैं, तो प्राथमिकताओं का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि राज्य विकास कार्यों और औद्योगिक विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर ऋण चुटाने में सक्षम है, तो उसी अनुपात में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की महंगाई के अनुरूप समीक्षा, असंगठित कारखाना श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय सुरक्षा, और नए पात्र लाभार्थियों के पंजीयन पर भी गंभीर विचार होना चाहिए। विकास का अर्थ केवल निवेश और उद्योग नहीं, बल्कि उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और वृद्ध नागरिक की आर्थिक सुरक्षा भी है। सड़कों और कारखानों के साथ-साथ आम नागरिक की सामाजिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हो – यही संतुलित और संवेदनशील शासन की पहचान है।



राजनेता

योगेंद्र सिंह परिहार

स्वतंत्र लेखक

मध्य प्रदेश की ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में उन विरले नेताओं के नामों को उंगलियों पर गिना जा सकता है जिनका जुड़बट साथी जमीन और आम कार्यकर्ताओं से है। इस फेहरिस्त में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे जितने कद काठी से मजबूत हैं उतने ही बौद्धिक रूप से जहिकेन और सुलझे हुए राजनेता हैं। उनकी विश्वप्रसंग शक्ति का तो पूरा देश कायल है। दशकों पुराने मिलने वालों को नाम से पुकारना उनकी विशिष्ट पहचान है।

दिग्विजय सिंह जी ने संपन्न व राजसी पृष्ठभूमि होने के बावजूद वैभव के स्थान पर संघर्ष को प्राथमिकता दी। उनकी राजनीति विशुद्ध जमीनी और जन सेवा को समर्पित रहती है। इसीलिए तो उन्हें जमीनी राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। उन्होंने सत्ता और संगठन में संगठन को सर्वोपरि रखा। दिग्विजय सिंह जी ने संगठन के कार्यों में उनकी रुचि से जुड़े एक बड़ा रोचक वाक्या सुनाया। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी जी ने पूरे देश में सक्रिय युवा नेतृत्व की खोज के लिए टैलेंट हंट का आयोजन किया था जिसकी जिम्मेदारी तरुण गोरोई जी को दी गई थी। जिसमें देश भर से युवाओं का चयन किया गया उनमें से एक वे भी थे। वे बताते हैं कि उस वक्त उनका इंटरव्यू राजीव गांधी जी ने स्वयं लिया था। राजीव जी ने इंटरव्यू के दौरान दिग्विजय सिंह जी से पूछा कि 'आप क्या करना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। राजीव जी ने कहा कि मेरे साथ काम करने के लिए आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आप कहें तो मैं आज रात को भोपाल पहुंचकर इस्तीफा दे देता हूं। हालांकि राजीव जी ने उनका इस्तीफा उस वक्त नहीं लिया। और बाद में राजीव गांधी जी ने उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया।'

मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य तब जिसमें छत्तीसगढ़ भी

राजनीति के पुरोधा दिग्विजय सिंह जी, जमीनी संघर्ष और जन सेवा के पर्याय हैं

शामिल था, वहां संगठन को खड़ा करना हंसी खेल नहीं था। तब दिग्विजय सिंह जी ने एक गाड़ी में बोयिया बिस्तर बांधकर पूरे प्रदेश को नाप दिया था। गांव-गांव रात रुक कर लोगों के मिजाज को समझा। ब्लॉक स्तर पर जाकर अच्छे लोगों को ढूंढकर पदों पर बैठाया। जमीन पर इतना काम किया कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस दिखाई देने लगी। उन्होंने प्रदेश की तारीफ को समझा, विधानसभा चुनाव लड़ने लायक नेताओं को तैयार किया। परिणाम स्वरूप 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी।

ताज्जुब ये था कि 1993 में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले किसी ने दिग्विजय सिंह जी के मुख से मुख्यमंत्री बनने की बात तक नहीं सुनी थी। क्योंकि उन्होंने इस बात का कभी शोर नहीं मचाया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है बल्कि जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने एकाग्रता के साथ चिड़िया की आंख को भेदने का लक्ष्य बनाया था उसी तरह दिग्विजय सिंह जी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का एकमेव लक्ष्य तय कर रखा था। अपने संकल्प के प्रति गंभीरता के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा रहने की वजह से ही उन्होंने सरकार बनाने के लक्ष्य को पूरा किया था।

दिग्विजय सिंह जी में अपार संगठन क्षमताएं हैं। वे अक्सर कहते हैं जिस पार्टी के पास कैडर, कार्यकर्ता और कार्यक्रम होंगे वो पार्टी हर परिस्थिति में सफल होगी। दिग्विजय सिंह जी राजनीति के शुरुआती दौर से ही संगठन के विभिन्न पदों पर रहे। 1971 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। 1972 में गुना जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बने। 1978 से 1980 तक मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के महामंत्री और प्रभारी बनाए गए तब भंवर सिंह पाते जी प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दिग्विजय सिंह जी विधायक थे। वे 1985 से 1988 तक एवं 1991 से 1994 तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2004 के बाद लगभग 13 साल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे। उसी दौरान वे कई राज्यों के संगठन प्रभारी भी थे। यही कारण है कि संगठन के छेदे से बड़े पदों पर रहने की वजह से वे संगठन की बारीकियों को बहुत अच्छे से

समझते हैं। संगठन को मजबूत करने का उनका हमेशा एक ही फार्मूला रहा, संगठन को स्वायत्त बनाना और उसका विकेंद्रीकरण किया जाना। वे विकेंद्रीकरण के इतने बड़े हिमायती थे कि जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने राजीव गांधी

यह उनकी पूर्णतः एक आध्यात्मिक और निजी साधना थी, किंतु इस कठिन तपस्या के दौरान अनगिनत गांवों और मजदूरों से गुजरते हुए उन्होंने जो जन-संवाद किया, उसने प्रदेश की जनता के मन में उनके प्रति अगाध विश्वास भर दिया।

जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला। विनम्रता के साथ यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि दिग्विजय सिंह जी की 'पैदल नर्मदा परिक्रमा' रूढ़ी मंथन से अमृत के रूप में जनता और कांग्रेस नेताओं के बीच में आत्मिक जुड़बट उभर कर सामने आया और फिर जन-आशीर्वाद ने 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की राह प्रशस्त की।

दिग्विजय सिंह जी की धार्मिक पदयात्रा के अनुभव का लाभ देश ने तब भी देखा, जब राहुल गांधी जी की 'भारत जोड़े यात्रा' के प्रबंधन व संचालन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उस एक पदयात्रा ने राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कायापलट कर दिया। लोगों ने पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी जी को करीब से देखा तब उन्हें पता लगा कि राहुल जी के बारे में उन्हें झूठ बताया जाता रहा। न्यूट्रल एम्यूनिवर्सिटी द्वारा राहुल गांधी जी को गलत ठहराने का एक पंडित रचा गया, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही है। भारत जोड़े यात्रा से ही राहुल गांधी जी की छवि और निखरकर सामने आई। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी ने बखूबी निभाई। नर्मदा तट की पार्कडिंग से लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सड़कों तक, दिग्विजय सिंह जी ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल सत्ता के गलियारों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि जमीन पर पसीना बहाने वाले एक सच्चे वैचारिक तपस्वी हैं।

दिग्विजय सिंह जी की संगठन में पकड़ इसीलिए भी है कि वे नेताओं-कार्यकर्ताओं में समन्वय और आपसी तालमेल बनाने में माहिर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1993 से 2003 तक 10 साल चली कांग्रेस की दिग्विजय सरकार रही। दिग्विजय सिंह जी की समन्वय शक्ति का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी दिग्विजय नेताओं के बीच संतुलन बनाते

हुए वे 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उस दौर में मध्य प्रदेश की राजनीति में अर्जुन सिंह जी, मोती लाल बोरा जी, माधवराव सिधिया जी, विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, कमलनाथ जी, सुभाष यादव जी, श्रीमती जमुना देवी जी व शिवनाथ सिंह सोलंकी जी जैसे प्रभावशाली नेताओं का अच्छा खासा वर्चस्व था और इन शीर्षस्थ नेताओं के साथ बिना तालमेल बनाए सत्ता के शिखर पर बने रहना आसान कार्य नहीं था। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की समन्वय क्षमता ने वो करिश्मा भी कर दिखाया था।

दिग्विजय सिंह जी हर कार्यकर्ता को जमीन से जुड़े रहने के लिए पंच 'स' का अचूक मुखड़ा बताते हैं। संपर्क, संवाद, समन्वय, सामंजस्य और सकारात्मक सोच। यदि हर कार्यकर्ता और नेता ये मुखड़ा अपना ले तो उसके बाद उन्हें सफलता हासिल न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वे यह भी बताते हैं कि नेताओं को चाहिए कि वे खिलाफ बगवात करने को सुनना भी सीखना चाहिए, यदि आपने जनता और पार्टी कार्यकर्ता की बात ध्यान से सुनी ली तो काम बताने वाले को उतने में ही संतोष मिल जाता है।

संगठन की मजबूती की पैरवी करने वाले दिग्विजय सिंह जी की खास बात यही है कि वे पक्षे गांधी-नेहरू वादी नेता हैं, वे कांग्रेस की हर टूट में अटूट रहे अयोग्य विचारधारा को उन्होंने हर क्षण जिया। वे दिल से ये बात मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें खूब दिया, इसीलिए पार्टी के खिलाफ बगवात करने के बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते। हां, सांगठनिक स्तर पर सुधार की बात वे करते रहते हैं पहले भी करते थे और अपने मातृ संगठन की भलाई के लिए हमेशा करते रहेंगे जिसमें किसी को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए और न बुग मानना चाहिए।

28 फरवरी को कांग्रेस संगठन की रीढ़, कार्यकर्ताओं के अभिभावक एवं जन-जन के लाडले जनप्रतिनिधि राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदर्शपूर्ण दिग्विजय सिंह जी का जन्मदिवस है। हम उन्हें जन्मदिवस पर ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और सफल व सक्रिय दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।

इस युग में मां नर्मदा ही साक्षात् हैं, जैविक खेती कृषि उन्नति के आवश्यक है, युवाओं को सांत्विक बनना जरूरी दादा गुरु



सोहागपुर। निराहार समर्थ दादा गुरु सोहागपुर ब्लाक में समीपवर्ती नर्मदा नदी के विभिन्न घाटों एवं ग्रामों होकर माखनगढ़ ब्लाक में नर्मदा नदी घाटों से होकर ग्राम सतवास पहुंचे। यहां जिला जनपद पंचायत सदस्य एवं वरिष्ठ पत्रकार हाकमसिंह पटेल भोपाल ने दादा गुरु का ग्रामीणों के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर समर्थ दादा गुरु ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर दादा गुरु ने ग्रामीणों से कहा कि इस युग में मां नर्मदा ही साक्षात् हैं। ग्रामों में जैविक कृषि समृद्धि एवं उन्नति के लिए आवश्यक है। आपने आह्वान किया कि किसान जैविक खेती को अपनाएं। गऊ माता की रक्षा की सेवा करेंगे तो समाज, परिवार, गांव की रक्षा अपने आप हो जाएगी। आपने युवाओं पर भी अपनी सटीक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को शुद्ध सांत्विक बनने की अहम जरूरत है। खानपान से दूषित भ्रमराह करने वालों को सत मार्ग पर लाना होगा। आपने अपने सारगर्भित उद्बोधन में मां नर्मदा को सर्वोच्च स्थान दिया। आपने अंत में कहा कि मां नर्मदा की परिक्रमा निरंतर रहेगी तथा धर्म और प्रकृति के संरक्षण-संवर्धन के लिए मेरा पूर्ण समर्पण रहेगा। इस अवसर पर ग्राम सतवास ही नहीं आस-पास के हजारों नागरिक एवं मातृशक्ति उपस्थित थीं। उल्लेखनीय है कि दादा गुरु निराहार रहकर लगातार नर्मदा परिक्रमा कर रहते रहते हैं। उनके साथ भारी संख्या में नागरिक एवं मातृशक्ति भी परिक्रमा में शामिल रहते हैं।

जिला नर्मदापुरम में आगामी त्यौहारों पर अधिकारियों की ड्यूटी

सोहागपुर। जिला नर्मदापुरम में आगामी त्यौहारों पर मार्च में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार, 02 मार्च सान पर्व, 03 मार्च, होलिका दहन, सान दान, वृत्त पूर्णिमा, 03 मार्च घुरंडी (होली उत्सव), 04 मार्च बसंत उत्सव, 08 मार्च संपांचमी, 18 मार्च चैत्र अमावस्या, 19 मार्च चैत्र नवरात्र प्रारंभ, गुडी पड़वा, 20 मार्च झुलेलाल जयंती, वैती चांद, 21 मार्च ईद-उल-फितर, 27 मार्च रामनवमी, श्री दुर्गा नवमी एवं 31 मार्च महावीर जयंती के अवसर पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम राजीव रंजन पाण्डे ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं अधिकारियों की ड्यूटियां निर्धारित की हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी नर्मदापुरम श्री पाण्डे ने सुश्री प्रियंका भल्लावी को सोहागपुर, आंकप खान (आईएसए) अनुविभागीय दण्डाधिकारी पिपरिया, नीलेश शर्मा अनुविभागीय दण्डाधिकारी इंटासरी, विजय राय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी मालवा, जय सोलंकी अनुविभागीय दण्डाधिकारी नर्मदापुरम एवं देवेन्द्र प्रताप सिंह सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम की ड्यूटी लगाकर अपने-अपने अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले घाट स्थलों पर कार्यपालिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा है।

शंकरलालजी राठौर का देहांत होने पर राठौर परिवार द्वारा धार शहर का 32वां नेत्रदान

धार। धार के दौलत नगर निवासी 72 वर्षीय श्री शंकरलालजी राठौर का 26 फरवरी को उपचार के दौरान देहांत हो गया था। दुख की इस घड़ी में उनके पुत्र सुनील, अनिल, योगेश एवं उनके अन्य परिवार जनों ने उनके नेत्रदान का निर्णय किया। इस हेतु धार मानव सेवा कल्याण सेवा समिति से समर्थ किया गया। समिति द्वारा भोज हॉस्पिटल के नेत्र विभाग के डॉ.



सौरभ बैरासी और उनकी सहायिका पूर्णिमा के सहयोग से उनके नेत्रदान की प्रक्रिया अल्प समय में पूर्ण की। इस नेत्रदान से 2 से 4 लोगों को आंखों में रोशनी प्राप्त होगी जो कि मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही पुण्य का कार्य है। समिति द्वारा धार नगर में किया गया यह 32वां नेत्रदान है। इस नेत्रदान हेतु समिति द्वारा राठौर परिवार का आभार व्यक्त किया गया और नेत्रदानी श्री शंकरलालजी राठौर को श्रद्धांजलि दी गई।

अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ पिता करता था दुष्कर्म

कलयुगी पिता ने हवालात में किया आत्महत्या का प्रयास

बैतूल। मुलताई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 10 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने ही पिता पर लंबे समय से अनुचित कृत्य (दुष्कर्म) करने, उड़ाने धमकाने एवं जान से खत्म करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पिता ने पुलिस लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बैतूल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जहां से उसे एमएस भोपाल रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी को डायल 112 पर नाबालिग बालिका की मां ने सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा उसकी 10 वर्षीय बेटी को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया जा रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और कमरे को खुलवाकर पीड़िता को पिता से चंगुल से मुक्त कराया और आरोपी को मुलताई थाना लेकर आए। डायल 112



के साथ ही नाबालिग बालिका अपनी माता के साथ थाना मुलताई आई और रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 65(2), 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं 5(एल)/6, 5(एम)/6, 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उदा-धमकाकर करता था अनुचित कृत्य - नाबालिग बालिका ने बताया कि उसके पिता द्वारा जब-जब उसकी मां घर पर नहीं होती थी, तब-तब लंबे समय से उसके साथ अनुचित कृत्य

किया जा रहा है तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती था। नाबालिग द्वारा पूर्व में अपनी मां से पिता के द्वारा किए गए अनुचित कृत्य की जानकारी देने पर आरोपी द्वारा उसकी मां को भी कई बार मारा-पीटा गया एवं धमकाया गया। नाबालिग बालिका ने पिता पर लंबे समय से दुष्कर्म करने एवं बताने पर उड़ाने-धमकाने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। जिसकी शिकायत नाबालिग बालिका ने थाने में दर्ज कराई है।

मां ने डायल 112 से ली मदद - कलयुगी पिता द्वारा दरवाजा न खोलने पर

श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंदौर, स्टडी आईव्यू के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यशाला का समापन

विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित

सुबह सवेरे संवाददाता। श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ कॉमर्स इंदौर एवं स्टडी आईव्यू आईएसए इंदौर के संयुक्त सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिलि सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु समुचित दिशा-निर्देश एवं रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना था।

कार्यशाला के दौरान सिविल सेवा परीक्षा की संरचना, चयन प्रक्रिया, अध्ययन सामग्री का चयन, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन तकनीक एवं सफलता की प्रभावी रणनीतियों पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। प्रथम दिवस पर विशेषज्ञ गौरव शर्मा एवं हरिसिंह राजपूत द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा की बारीकियों से अवगत कराया गया। द्वितीय एवं तृतीय दिवस पर सौरभ यादव एवं अंशुल तिवारी सर ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते

हुए तैयारी के व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके प्रश्नों का समाधान किया।



समापन सत्र में विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर स्टडी आईव्यू के मैनेजर रवि शंकर दुहैलिया एवं अंकित चौरसिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्था की ओर से निःशुल्क कोर्स उपलब्ध कराने का आभार प्रदान किया। अंतिम दिवस पर विद्यार्थियों के लिए एक

स्कॉलरशिप टेस्ट भी आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से मेधावी विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।

कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. परितोष अवस्थी, समस्त समिति समन्वयक प्रो. विभोर एरें, प्रो. डॉ. राकेश उपाध्याय, बीए विभाग संयोजक प्रो. हितेश चौधरी सहित अन्य प्राध्यापकगण उपस्थित रहे।

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए सिविल सेवा का एक सशक्त करियर विकल्प के रूप में समझा तथा विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महाविद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी स्टडी आईव्यू के सहयोग से ऐसे आयोजन निरंतर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आभार प्रदर्शन प्रो. श्रद्धा मानधन्या द्वारा किया गया। तकनीकी सहयोग प्रो. सत्यम पंचाल द्वारा प्रदान किया गया।

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने 107 करोड़ की लागत से सागौर एवं मानपुर के दो रेलवे ओवर ब्रिज जनता को किये समर्पित

आदिवासी अंचल में रेल विकास से खुलेगा प्रगति का नया द्वार

धार। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सागौर एवं मानपुर स्थित ब्रिज क्रमांक 234 ए एवं 221 ए के दो रेलवे ओवर ब्रिजों का लोकार्पण कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया गया। लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन दोनों ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री महिषा एवं बाल विकास विभाग सावित्री

ठाकुर ने कहा कि ये ओवर ब्रिज क्षेत्र की जनता को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगे। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की यह मांग थी, जो आज पूर्ण हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिवस पूर्व ही उन्होंने इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन के प्रगतिरत कार्यों का विशेष ट्रॉली में बैठकर विस्तृत निरीक्षण किया था तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्माण कार्य समय-समय में एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। आज इन ओवर ब्रिजों का लोकार्पण उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ठाकुर ने उपस्थित जनसमुदाय को विश्वास दिलाया कि सागौर ही लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को रेलवे परिवहन की सीधी सुविधा मिलने जा रही है। रेल संपर्क प्रारंभ होने



से आदिवासी अंचल में व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नए अवसर विकसित होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

बेटी से दुष्कर्म आरोप में गिरफ्तार

खेती कंबल को फाड़ कर उसका फंद बना कर आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। आरोपी की हालत गंभीर होने पर उसे बैतूल जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, फंदे के कारण आरोपी को सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो रही है, जिसके चलते उसे इंक्यूबेट (वेंटिलेटर सपोर्ट) दिया गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे जल्दत पड़ने पर पुलिस द्वारा भोपाल एम्स रेफर करने की तैयारी की जा रही है। घटना के बाद से बैतूल जिला अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। पुलिस इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की पहचान गोपनीय रखकर आगे की कार्रवाई कर रही है।

इनका कहना है - पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया, उससे थाने के लॉकअप में कंबल को काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भर्ती किया गया।

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडव में घर-घर तक पहुँच रहा है माँ नर्मदा का जल

धार। ऐसी किंवदंती है कि रानी रूपमती अपने महल से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के दर्शन किया करती थीं। आज उसी ऐतिहासिक धरा मांडव में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा हर घर तक माँ नर्मदा का स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की दिशा में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि स्थापित की गई है।



गौरतलब है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी इकाई इंदौर के अंतर्गत संचालन एवं संधारण अवधि के दौरान मांडव जल प्रदाय परियोजना का कुशल संचालन निरंतर जारी है। इस परियोजना के अंतर्गत धरमपुरी जल शोधन संयंत्र से दो चरणों में पानी को लिफ्ट करते हुए लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित मांडव तक पेयजल पहुँचाया जा रहा है, जिससे पर्यटन नगरी में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। धरमपुरी स्थित 2.4 एमएलडी क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र से मांडव तक जल पहुँचाने के लिए लगभग 550 मीटर की ऊँचाई तक पानी लिफ्ट किया जाता है, जो तकनीकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सड़क, रेल, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। केंद्र सरकार अंतिम पॉन्क के व्यक्ति तक विकास की पहलू को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सागौर एवं मानपुर के ये ओवर ब्रिज केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक हैं। आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र में और भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जिससे क्षेत्र समग्र प्रगति की ओर अग्रसर हो सके।

कार्यक्रम में निलेश भारती, रेलवे डीआरएम अश्विनी कुमार सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, आमजन एवं कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

स्क्रीनिंग शिविर हडिया में दिव्यांगजनों की स्क्रीनिंग की गई

हरदा (निप्र)। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित सभी पेंशन योजनाओं इंद्रिा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंद्रिा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, इंद्रिा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के पेंशन फार्म तैयार कर पेंशन स्वीकृत करने एवं उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने हेतु जिले में स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री कमलेश सिंह ने बताया कि बुधवार को दिव्यांगजनों के चिन्हांकन एवं दिव्यांग प्रमाण-पत्र तैयार कराने हेतु स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के अधिकारी विशेषज्ञों द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से 151, शिविर स्थल पर 161 एवं विद्यालय में 154 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार पेंशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदाय किया गया।

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरुद्ध 8 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के मंगलवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरुद्ध कार्यावाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दाने व वृत् टिमरनी के ग्राम इकडालिया, गोगिया, कामलिया दाबा, शीतल दाबा, राजपूर दाबा, करताना, छीपाना, छीपाना व ग्रीदागाव में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 18 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 21 पाव देशी शराब एवं 560 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 8 प्रकरण दर्ज किये। जप्त महुआला का अनुमानित बाजार मूल्य 61175 रुपये है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विकास कार्यालय इंदौर द्वारा जिला प्रशासन नर्मदापुरम के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शासकीय सभागोय आईटीआई नर्मदापुरम में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थितजनों को उद्यमिता, वित्तीय सहायता, ई-कॉमर्स, शासकीय योजनाओं, कौशल विकास, मार्केटिंग, लोन प्रोसेस संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीयें दी गईं। भारतीय डाक द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने हेतु वयूआर कोड लाभार्थियों को निशुल्क उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम में एमएसएमई इंदौर से सहायक निदेशक श्री गौरव गोयल एवं श्री विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्रबंधक श्री देवेन्द्र रघुवंशी, अग्रणी जिला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से श्री रमेश वाघेलिया, भारतीय डाक विभाग से श्री प्रदीप कुमार एवं श्री तिर्की, शासकीय सभागोय आईटीआई नर्मदापुरम से प्राचार्य संजय टेकाम, हथकच्चा विभाग से दिव्या थांगले, एनएसडीसी से श्री जिनेंद्र, एमपीआईडीसी से श्री शुभम गुप्ता एवं ट्रेनिंग संस्थान सीएफटीआई से श्री सोनभ श्रीवास्तव सहित करीबन 180 हितग्राहियों ने भाग लिया। समस्त अधिकारियों ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की विस्तृत जानकारी दी और विभिन्न समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया।

मेहनत और सकलप से बदली जिंदगी: खुशी आजीविका समूह से जुड़कर श्रीमती चम्पा कुशवाहा बनी आत्मनिर्भर

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले के विकासखंड सिवनीमालवा, ग्राम नंदरवाड़ा में संचालित 'खुशी आजीविका समूह' की सदस्य श्रीमती चम्पा कुशवाहा ने आजीविका मिशन से जुड़कर आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल पेश की है। चम्पा कुशवाहा ने अपने जीवन की शुरुआत अनेक आर्थिक चुनौतियों के बीच की। परिवार की आजीविका चलाने के लिए वे मजदूरी करती थीं, जिससे उन्हें प्रतिमाह लगभग 1,000 से 2,000 रुपये तक की आय ही हो पाती थी। वर्ष 2017 में ग्राम में गठित स्व-सहायता समूहों की जानकारी मिलने पर मिशनकर्मियों एवं ग्राम की महिलाओं के प्रोत्साहन से उन्होंने 'खुशी आजीविका समूह' से जुड़ने का निर्णय लिया। समूह से जुड़ने के पश्चात उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने आटा चक्की का व्यवसाय प्रारंभ किया। इस उद्यम से उनकी मासिक आय 5,000 से 7,000 रुपये तक पहुंच गई। आगे बढ़ते हुए चम्पा ने किराना दुकान एवं गल्ला खरीदी का कार्य भी शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन से व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई और आय के नए स्रोत विकसित हुए। वर्तमान में चम्पा कुशवाहा को आटा चक्की एवं किराना दुकान से नियमित आय प्राप्त हो रही है, साथ ही गल्ला खरीदी से अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है।

विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु वर्ग के कल्याण और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: राज्यमंत्री

सीहोर (निप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने, शिक्षा एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा योजनाओं का लाभ अंतिम पविक्त के व्यक्तित्व तक पहुंचाने के लिए प्रभावी रणनीति के साथ कार्य किया जा रहा है।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक-6 में विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घुमंतु कल्याण विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, नवाचरो और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर सागर (बण्डा) विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी, संधवा विधायक श्री मोंटी सोलंकी और विभाग के संचालक श्री बुद्धेश वेद्य उपस्थित रहे।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि विभाग द्वारा इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। शासन की कल्याणकारी योजनाओं के समेकित विकास के लिये प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जिलों में 'जन

विदिशा जिले में नरवाई प्रबंधन की विशेष पहल जागरूकता, तकनीक और समन्वय से बना मॉडल जिला

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश का विदिशा जिला वर्ष 2026 में नरवाई प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष पहल करते हुए एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। रबी फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने की समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के संयुक्त प्रयासों से व्यापक कार्ययोजना लागू की गई है, जिसमें जागरूकता, आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

जेएफएस पोर्टल से हजारों किसानों को मिली सुविधा

जिले में जेएफएस (जस्ट फार्म सर्विस) पोर्टल के माध्यम से नरवाई प्रबंधन को गति मिली है। जिले में 113 कस्टम हार्विंग सेंटर पोर्टल से जुड़े हुए हैं, जिनमें 9854 से अधिक यंत्र प्रदाता और 1 लाख 4 हजार से अधिक किसान पंजीकृत हैं। पोर्टल के माध्यम से अब तक 11 हजार 470 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कृषि यंत्रों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इस पोर्टल पर हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रीपर, रोटावेटर, श्रेशर और हार्वेस्टर सहित कुल 2564 कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान : विदिशा जिले में वर्तमान में 528 से अधिक कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जबकि वर्ष 2025-26 में 1435 नए यंत्रों



का लक्ष्य रखा गया है। इनमें प्रमुख रूप से रु-153 सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर, 131 रोटावेटर, 997 हार्वेस्टर, 73 जीरो टिल सीड ड्रिल, 52 मल्ट्र, इन यंत्रों के माध्यम से 2476 से अधिक किसानों द्वारा नरवाई प्रबंधन किया जा चुका है।

जागरूकता अभियान से बदल रही किसानों की सोच : विदिशा जिले में किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर पर लगातार बैठकें, प्रशिक्षण और प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 153 सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर का वितरण किया जा चुका है। 997 हार्वेस्टर उपलब्ध कराए गए हैं। 48 एफपीओ और कस्टम हार्वरिंग

सेंटर के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। इन प्रयासों से किसानों में नरवाई न जलाने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक लाभ : नरवाई प्रबंधन से जहां पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई है, वहीं किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नरवाई को मिट्टी में मिलाने से, मिट्टी की उर्वरता बढ़ रही है। उर्वरकों की लागत कम हो रही है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही नरवाई से चारा और अन्य उपयोग भी संभव हो रहे हैं।

प्रशासन की सतत निगरानी और समन्वय : जिला प्रशासन द्वारा नरवाई प्रबंधन के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने वसीम खान का जीवन बदला, 10 लाख के ऋण से शुरु की वैलिंग वर्कशॉप



विदिशा (निप्र)। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वयं का व्यवसाय शुरू करने व आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस योजना का प्रशिक्षण आईटीआई विदिशा से लोक स्थिथ जांब रोल में प्राप्त किया, योजना के तहत उन्होंने 10,00,000 दस लाख रुपए की ऋण राशि प्राप्त की। जिसमें उन्होंने लटेरी में अपना वैलिंग वर्क शॉप प्रारंभ किया और आज वह मध्य प्रदेश के लगभग 5 जिलों में अपनी वर्कशॉप में तैयार सामग्री सहित अन्य पांच जिलों में सप्लाइ करके इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है और आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने में जीवन में बड़े बदलाव किए हैं।

विदिशा जिले के लटेरी तहसील के श्री वसीम खान बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अपने क्षेत्र के जनपद कार्यालय से जानकारी प्राप्त की थी। फिर उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रशिक्षण आईटीआई विदिशा से लोक स्थिथ जांब रोल में प्राप्त किया, योजना के तहत उन्होंने 10,00,000 दस लाख रुपए की ऋण राशि प्राप्त की। जिसमें उन्होंने लटेरी में अपना वैलिंग वर्क शॉप प्रारंभ किया और आज वह मध्य प्रदेश के लगभग 5 जिलों में अपनी वर्कशॉप में तैयार सामग्री सहित अन्य पांच जिलों में सप्लाइ करके इस योजना ने उनका जीवन बदल दिया है और आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने में सहायता प्रदान की है।

मिशन प्रबंधन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला स्तरीय सेमीनार एवं पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ

नर्मदापुरम (निप्र)। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (स्कूपडू) योजना के घटक मिशन प्रबंधन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत लगभग सात सौ कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा दो दिवसीय जिला स्तरीय सेमीनार एवं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन एम पी एग्री फार्म माखननगर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद श्री दर्शनसिंह चौधरी ने किया। कार्यक्रम में म.प्र. तैराकी संघ के अध्यक्ष श्री पीयूष शर्मा, श्री अजीत मण्डलौई सभापति जिला कृषि स्थायी समिति जिला पंचायत नर्मदापुरम, श्रीमति सावित्री बाई परनामे जनपद अध्यक्ष माखननगर, श्री निखलेषा चतुर्वेदी, श्री योगेंद्र सिंह राजपुत, श्री विपिन यादव, श्री कुवर सिंह यादव, श्री मनीष चतुर्वेदी, आदि जनप्रतिनिधी गण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में उप संचालक उद्यान श्रीमती रीता उखेके द्वारा जिले में संचालित विभागीय योजनाओं सब्जी, मसाला, पुष्प, फल, मखाना, माईको स्टोर्गेशन, ऋक्षस्व आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला स्तरीय सेमीनार के प्रथम दिवस सेमीनार में मखाना की खेती, हाईटेक हार्टिकल्चर, जैविक खेती, पॉली हाउस में सब्जी/फूल उत्पादन, प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र छिंदवाड़ा के श्री आर एल राजत, कृषि महाविद्यालय



पवारखेड़ा के वैज्ञानिक डॉ. विजय अग्रवाल, जिला रिसोर्स पर्सन श्री सुमन्त निवारे, सुश्री विजयालक्ष्मी ने कृषकों को जानकारी दी।

सांसद श्री चौधरी ने सृष्टि हार्टिकल्चर के बागवानी से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया और उपस्थित कृषकों को खेती से संबंधित शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी कृषकों को उद्यानिकी विभाग की संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से संबोधित किया। एम पी एग्री में मखाना प्रदर्शन प्लाट, उद्यानिकी विभाग के स्टाल, पुष्प प्रदर्शनी सृष्टि हार्टिकल्चर, आजीविका मिशन, माईको इरीगेशन

अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं, ऋक्षस्व के उत्पादों के स्टाल कार्यक्रम में लगाये गये जिनका अतिथिगणों एवं कृषकों द्वारा अवलोकन किया गया।

जिला स्तरीय कार्यक्रम संचालन श्रीमति आरती चौरे, श्री के के रघुवंशी एवं सुश्री विजयालक्ष्मी बलवडें के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, एम पी एग्री माखननगर, आजीविका मिशन के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य जिलों छिंदवाड़ा सिवनी, बालाघाट, रायसेन के कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन एवं आभार प्रदर्शन श्रीमति रीता उखेके उप संचालक उद्यान नर्मदापुरम द्वारा किया गया।



अभियान परिषद' के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, मंदसौर, रायसेन, राजापुर एवं राजगढ़ जिले शामिल हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बताया कि राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु समुदाय कल्याण एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित 'सीड' परियोजना के आवास घटक के तहत प्रदेश में 3047 पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इसके अंतर्गत 7 जिलों के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 100 प्रतिशत अनुदान (केंद्र सरकार) दिलाने के लिए एम.ओ.यू. पर सहमति बन

चुकी है। केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय बोर्ड के माध्यम से 'सीड परियोजना' में समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है। 'बडी फॉर स्टडी' संस्था के माध्यम से विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग, म.प्र. लोका सेवा आयोग, एएसएससी, ग्रामीण बैंक, क्लेट, जेईई, नीट और एनडीए जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना से 94 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यवाही प्रचलन में है।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में निवासरत विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध घुमंतु समुदायों के परिवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल कर दिया गया है। अब अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि कोई भी पात्र हितग्राही लाभ से वंचित न रहे। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर महिला आईटीआई में भाषण एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन

बैतूल (निप्र)। शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, मध्यवर्ती क्षेत्र (भारत सरकार परमाणु उर्जा विभाग) के तत्वावधान में 'चुमेन इन साइंस विकसीत भारत' विषय पर क्विज एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक सोच, नवाचार की भावना तथा राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम परमाणु उर्जा विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी श्री विजय कुमार, श्री प्रकाश बेदिया, श्री प्रकाश मुखर्जी, श्री स्मृतिरंजन साहू, श्री सतीश चैनमशेंद्री एवं संस्था प्राचार्य श्री अजीश पन्डे एवं वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी श्री रेवाशंकर पंडारे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संस्था प्राचार्य श्री अजीश पन्डे ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वैज्ञानिक अधिकारी श्री विजय कुमार ने छात्राओं को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने, अनुसंधान एवं नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज महिलाएं परमाणु विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। श्री प्रकाश बेदिया ने बताया कि आज महिलाएं वैज्ञानिक प्रोफेसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं रिसर्च हेड के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे मिसाइल या रक्षा विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा एवं जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो महिलाओं की सक्रिय भूमिका बढ़ते जा रही है।

कृषि विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं।

विदिशा बन रहा नरवाई प्रबंधन का आदर्श : विदिशा जिले में नरवाई प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। आधुनिक तकनीक, पर्याप्त संसाधन और किसानों की बढ़ती जागरूकता से यह अभियान सफल हो रहा है।

यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक मजबूत कदम साबित हो रही है।

प्लोरोसिस से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने तथा पेयजल स्रोतों की नियमित जांच के कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने दिए निर्देश

रायसेन (निप्र)। राष्ट्रीय प्लोरोसिस निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय को-आर्डिनेशन बैठक कलेक्टर कार्यालय स्थित वीसी कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने चिकित्सा अधिकारियों से जिले में प्लोरोसिस से बचाव हेतु जागरूकता गतिविधियों, प्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों की जांच और उपचार संबंधी जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही प्लोरोसिस के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने तथा पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्रों को जिले में नियमित रूप से नलकूपों, ट्यूबवेल के पानी की जांच किए जाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने प्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के नमूनों की नियमित जांच करने और असुरक्षित स्रोतों को चिह्नित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लोराइड मुक्त, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही प्लोरोसिस से बचाव के लिए नागरिकों को संचावित डेंटल प्लोरोसिस से प्रभावित पाए गए। देते हुए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाए। इसके साथ ही प्लोरोसिस से प्रभावित मरीजों का



समुचित उपचार किया जाए तथा सतत मॉनीटरिंग भी की जाए। बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि जिले में करीब 354 ग्राम प्लोराइड से प्रभावित हैं, इनमें विकासखण्ड गैरतंजज के 88, सिलवानी के 93, बेगमगंज के 107, बरौली के 30, उदयपुर के 20, सांची के 10 और औबेदुल्लागंज के 02 ग्राम प्लोराइड से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगभग 106 ग्रामों में भ्रमण कर बच्चों तथा ग्रामीणों का परीक्षण किया गया। इनमें 3493 बच्चों का परीक्षण किया गया जिनमें लगभग 1114 बच्चे संचावित डेंटल प्लोरोसिस से प्रभावित पाए गए। जांच उपरांत 393 बच्चों में प्लोरोसिस की पुष्टि हुई है तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा चिन्हित

किए गए प्रभावितों को कैल्सियम एवं विटामिन सी की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सतत मॉनीटरिंग भी की जा रही है। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने निर्देशित किया कि जिले में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पानी की जांच हेतु प्रशिक्षण दिया जाए तथा फील्ड टेस्टिंग किट वितरित की जाए। बैठक में पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्रों श्री गिरीश कामले, महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बुजेश जैन, सिविल सर्जन श्री यशपाल सिंह बाल्यान, जिला प्लोरोसिस कंसल्टेंट एवं नोडल अधिकारी श्री एमडी भारती सहित स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, बीएमओ तथा बीपीएम उपस्थित रहे।



जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर कार्यालय के रेवा सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के दिशा-निर्देशन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सीईओ जिला पंचायत श्री हिमांशु जैन ने की।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरसिंह गेहलोत, डीएचओ डॉ. सुजन सेंगर, सिविल सर्जन डॉ. सुनीता कामले, डॉ. सुनीता नागेश, आरएमओ श्री गजेंद्र यादव, जिला परियोजना अधिकारी श्री ललित डेहरिया, जिला मीडिया प्रभारी श्री सुनील साहू, डीपीएम सुश्री कविता भोंई सहित समस्त सीबीएमओ, बीएमओ, सीडीपीओ, बीईई, बीपीएम तथा स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सीईओ श्री जैन ने स्वास्थ्य विभाग के 22 प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांकों की गहन समीक्षा की। इनमें गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन एवं चार अनिवार्य जांच, एनीमिक गर्भवती महिलाओं का समुचित प्रबंधन, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, नवजात शिशुओं की गृह भेंट, पूर्ण टीकाकरण, असंचारी रोगों की स्क्रीनिंग, टीबी जांच, सिकल सेल अभाव के प्रभावी क्रियान्वयन तथा स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता शामिल रहे। उन्होंने विकासखंडवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले विकासखंडों को 15 दिवस के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आगामी बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने वाले एएएम, सीएचओ, आशा कार्यकर्ता एवं संबंधित मॉनिटरिंग अधिकारियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति अथवा निलंबन की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश सीएमएचओ को दिए गए। साथ ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण सहित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं की भी समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। सीईओ जिला पंचायत के निर्देशानुसार श्रम विभाग की प्रतिनिधि सुश्री सरिता साहू द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता, मासिक अंशदान, लाभ, पंजीयन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की गई। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्रता अनुसार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने एवं शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया।

उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में एक साल के अंदर 17 बच्चों की मौत

हार्डकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब

उज्जैन (नप्र)। सेवा धाम आश्रम में पिछले एक साल के भीतर 17 बच्चों की मौत के मामले में हार्ड कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है। साथ ही सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है। खास बात तो यह है कि बच्चों की मौत के मामले में महिला बाल विकास विभाग के उज्जैन के कार्यक्रम अधिकारी को यह पता नहीं है कि कितने की मौत हुई है। न यह पता है कि मौत कैसे हुई है। अब अधिकारी आश्रम के निरीक्षण करने पहुंचे थे।

सेवाधाम आश्रम में हुई है बच्चों की मौत- दरअसल, पूरा मामला उज्जैन के अंबोदिया गांव स्थित सेवाधाम आश्रम का है। यहां निराश्रित, बुजुर्ग, मानसिक और शारीरिक दिव्यांगजनों को रखा जाता है। वर्तमान में यहां ऐसे 1200 लोग हैं, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस आश्रम पर मौत के मामले और अन्य गड़बड़ियों को लेकर समय-समय पर सवाल खड़े होते आए हैं। ऐसा ही मामला अब फिर सामने आया है।

एक साल पहले इंदौर में हुई थी बच्चों की मौत- करीब एक साल पहले 10 बच्चों की मौत के बाद इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद कर दिया गया था। बेहतर देखभाल का हवाला देकर यहां के 86 बच्चों को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था। चौकाने वाली बात ये है

कि इन 86 बच्चों में से 17 बच्चों की जान जा चुकी है। यही नहीं, सबकी मौत का कारण भी एक ही बताया गया- सांस लेने में तकलीफ।

शवदाह गृह के रिकॉर्ड की पड़ताल से खुला मामला- यह खुलासा उज्जैन जिला



अस्पताल और विद्युत शवदाह गृह के रिकॉर्ड की पड़ताल से हुआ है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार के निर्देश पर इंदौर के युगपुरुष आश्रम को बंद किया गया था। इसकी वजह थी कि जून-जुलाई 2024 में आश्रम में हैजे से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। युगपुरुष आश्रम बंद होने के बाद वहां रह रहे 86 विशेष बच्चों (34 लड़के और 52 लड़कियां) को उज्जैन भेजा गया। इनकी उम्र 5 से 23 वर्ष के बीच थी।

23 जनवरी 2025 से मौतें शुरू- शिफ्टिंग के एक माह में ही यानी 23 जनवरी 2025 से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। उज्जैन जिला

अस्पताल व शवदाह गृह के रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ। इससे सेवा-आश्रमों में बच्चों की स्थिति, इलाज और मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। उज्जैन के इलेक्ट्रिक शवदाह गृह के रिकॉर्ड में दर्ज नामों से पुष्टि होती है कि 17 की मृत्यु हो चुकी है।

हार्डकोर्ट ने लिया संज्ञान- वहीं, मीडिया में खबर आने के बाद यह मामला हार्ड कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने संज्ञान में लिया। एमपी हार्डकोर्ट ने इंदौर के युगपुरुष धाम से उज्जैन स्थित सेवाधाम आश्रम भेजे गए बच्चों की मौतों के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

दो सप्ताह में मांगा है जवाब- हार्डकोर्ट ने मुख्य सचिव, महिला और बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, कलेक्टर-एसपी उज्जैन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं सेवाधाम आश्रम के अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। उज्जैन सेवाधाम आश्रम की निरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद आगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

समिति कर रही है जांच- वहीं, इस घटना को लेकर जब महिला बाल विकास विभाग के उज्जैन जिला कार्यक्रम अधिकारी वृजेरा त्रिपाठी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग द्वारा घटना को संज्ञान में लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने वन विभाग के विजन डाक्यूमेंट का किया विमोचन



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2047- रीइमेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सस फॉर ए क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर पुस्तक का मुख्यमंत्री निवास में विमोचन किया। विजन@2047 राज्य में जैव विविधता समृद्ध, सामुदायिक सहभागिता आधारित वन प्रबंधन की दीर्घकालिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। प्रमुख सचिव वन श्री संदीप यादव ने बताया कि प्रदेश के वनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु-सहिष्णु तथा जैव-विविधता से समृद्ध आदर्श वनों के रूप में स्थापित करना विजन@2047 का लक्ष्य है। दृष्टि पत्र में वनों के संरक्षण और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। दृष्टि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आजीविका को सुरक्षित करने में सक्षम, समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में प्रदेश के वनों का संरक्षण किया जाएगा। दृष्टि पत्र में प्रदेश के वन क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग का यह दृष्टि पत्र भारत के पर्यावरणीय तथा विकास लक्ष्यों में निर्णायक योगदान देगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही एन अम्बाड़े, प्रबंध संचालक राज्य वन विकास निगम श्री एच यू खान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) श्री विभाष कुमार ठाकुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री शुभरजन सेन, प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्रीमती समीता राजौरा तथा संचालक वन विहार श्री विजय कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे।

यूनिफॉर्म-बुक खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल सकेंगे स्कूल

8 एसडीएम करेंगे कार्रवाई, कलेक्टर ने आदेश के साथ टीम भी बनाई



भोपाल (नप्र)। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले ही यूनिफॉर्म और बुक की खरीद-फरोख्त को लेकर भोपाल जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म-बुक को लेकर आदेश जारी किए हैं। 8 एसडीएम को जिम्मेदारी देते हुए कार्रवाई करने को कहा है।

आदेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य पेरेंट्स पर बुक, यूनिफॉर्म समेत स्टेशनरी खरीदने पर दबाव नहीं डाल सकेंगे। वर्तमान में कई स्कूल ऐसे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। नए सत्र में यह न हो, इसलिए कलेक्टर ह्व अनुभाग में एसडीएम समेत 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इसमें संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को शामिल किया गया है।

परीक्षा के बाद अप्रैल से खुलेंगे स्कूल- अभी स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, जो मार्च में भी होंगी। इसके बाद अप्रैल में स्कूल फिर से खुलेंगे। इसी दौरान पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म, बुक समेत अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। पिछले साल भी कलेक्टर सिंह ने नए शिक्षा सत्र से पहले आदेश जारी किए थे।

पन्ना में लुटेरी दुल्हन गिरोह के 9 लोग गिरफ्तार

शादी का झांसा देकर युवक को किया अगवा, फिर डरा-धमकाकर लूटे 1 लाख रुपए

पन्ना (नप्र)। पन्ना जिले में पुलिस ने अंतरराज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने शादी का झांसा देकर न केवल लूटपाट की, बल्कि अपहरण जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। बृजपुर थाना पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह कुंवारे युवकों को शादी का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। फिर डरा-धमकाकर या अपहरण कर उनसे मोटी रकम वसूलता था।

दो लड़कियों और एक महिला से मिलवाया

इस गिरोह का शिकार नयागांव धरमपुर निवासी 43 वर्षीय बसंत लाल त्रिपाठी बने। शादी की तलाश में उन्होंने लल्लू चौधरी नामक व्यक्ति से संपर्क किया था। योजना के तहत 23 फरवरी को त्रिपाठी पहाड़ीखेड़ा में लड़की देखने पहुंचे, जहां उन्हें दो लड़कियों और एक 1 लाख रुपए, टैबलेट लूट लिए शादी के नाम पर पैसे की मांग को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद गिरोह के सदस्यों ने त्रिपाठी के साथियों को डराकर भगा दिया। सफेद स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने त्रिपाठी को अगवा कर सुनसान रास्ते पर ले जाकर जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने त्रिपाठी से 1 लाख रुपए (20 हजार नकद और 80 हजार ऑनलाइन) और एक टैबलेट लूट लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पन्ना एसपी ने टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पहाड़ीखेड़ा बस स्टैंड पर घेराबंदी कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पृच्छाछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सुनियोजित तरीके से लुटेरी दुल्हन का नाटक रचकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे।

हार्ट-अटैक से आंखों के सामने पिता की मौत...

छतरपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एम्बुलेंस न मिलने के कारण एक बुजुर्ग की जान चली गई। हार्ट अटैक की आशंका में परिजन लोडर वाहन से अस्पताल ले गए। बेटा चलती गाड़ी में रास्ते भर पिता को सीपीआर देता रहा, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम तालगांव निवासी 65 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। वे अपने बेटे संतोष विश्वकर्मा के साथ शहर आए थे। इसी दौरान ग्राम बरकोंहा के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने लगी।

ट्रैफिक जाम में फंसी लोडर गाड़ी, देर से पहुंची अस्पताल- परिजन के अनुसार, माँके पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। मजबूरी में उन्हें एक लोडर वाहन से छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में हलत बिगड़ती देख बेटे संतोष ने चलती गाड़ी में ही सीपीआर देने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर में ट्रैफिक जाम के कारण वाहन को अस्पताल पहुंचने में परेशानी हुई। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर रास्ता साफ कराया, तब जाकर लोडर अस्पताल तक पहुंच सका।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी- डॉक्टरों ने बताया कि जब मरीज को अस्पताल लाया गया, तब उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जांच करने पर पता चला कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं सिविल सर्जन ने भी कहा कि मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। शुरुआती तौर पर मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। हालांकि सही कारण पोस्टमॉर्टम के बाद ही पता चल सकता था, लेकिन परिजन पोस्टमॉर्टम करवाए बिना ही शव को घर ले गए।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगी टीम

कलेक्टर ने टीम से कहा है कि किसी पेरेंट्स की जैसे ही शिकायत मिले, उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। संबंधित स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

इस बार होली गौकाष्ठ वाली

“मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, इस होली पर

आइए, एक पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाएं, लकड़ी की जगह ‘गौकाष्ठ’ को उपयोग करें। लकड़ी जलाने से पेड़ों की कटाई बढ़ती है, जबकि गौमाता के गोबर से बनी गौकाष्ठ प्राकृतिक, शुद्ध, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है।

आइए, मिलकर हरियाली बचाएं और स्वच्छ, जिम्मेदार होली मनाएं।”

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री



पर्यावरणीय होलिका दहन पुरस्कार

सरकार द्वारा हर जिले में पर्यावरण अनुकूल, गौकाष्ठ से होलिका दहन करने वाली समितियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

सभी सार्वजनिक होलिका दहन समितियों का आह्वान निःशुल्क पंजीयन के लिए अपने नगरीय निकाय/ जनपद पंचायत में संपर्क करें

गौकाष्ठ से होगा होलिका दहन बचेंगे गौवंश, पेड़ और वन

